



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]
No. 46]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 1981/फाल्गुन 11, 1902
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1981/PHALGUNA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

वर्ष 1981-82

वित्त मंत्री का भाषण

नई दिल्ली, 28 फरवरी 1981

भाग—क

पत्र सं वि०म० (ई०ए०डी०) यू०ओ०सं०फा० 15(3)-
डी० (डी०)/81

महोदय,

इस सम्मानित सदन के सामने मुझे एक बार फिर बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला है।

2. वर्ष 1981-82 का बजट एक ऐसी आर्थिक स्थिति में तैयार किया गया है जो बराबर कठिन बनी हुई है, लेकिन अब एक साल पहले की निराशाजनक परिस्थितियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। सदन में इस सप्ताह प्रस्तुत

की गई 'आर्थिक समीक्षा' में गत वर्ष के घटनाचक्र की विस्तृत समीक्षा की गई है। इसलिए मैं यहां आर्थिक स्थिति की उन मुख्य विशेषताओं की ही समीक्षा करूंगा जो अगले वर्ष के बजट की नीति का आधार हैं।

3. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जनवरी 1980 में जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था तब हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। उस समय वह 1979-80 के संकटापन्न आर्थिक कार्य-निष्पादन के कारण लड़खड़ा रही थी, जब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी और कीमतों में 21 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि हो गई थी। आधारभूत ढांचे की उपेक्षा और दुर्ब्यवस्था के कारण कोयला, बिजली और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकट की स्थिति पैदा हो गई थी।

4. इस भयानक स्थिति में, हमारा सर्वोपरि उद्देश्य यह था कि हालत को और ज्यादा बिगड़ने से रोका जाए और अर्थव्यवस्था को एक बार फिर स्थिरता और वृद्धि के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। यह कोई आसान काम नहीं था। 1979-80 के भयंकर सूखे और आधारभूत

ढाँचे की व्यवस्था की इकट्ठी समस्याओं की काली छाया 1980-81 में भी व्याप्त रही।

5. वर्ष 1980-81 में आधारभूत ढाँचे के कार्य-निष्पादन को सुधारने के प्रयत्नों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और दी भी गई। संकट से निपटने के लिए एक विशेष तंत्र की स्थापना की गई और उसमें इस क्षेत्र से सम्बन्धित सरकारी कार्रवाई पर नजर रखने और तालमेल बैठाने के लिए तथा स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की गई। इन प्रयत्नों का सुफल मिलने में कुछ समय लगा, लेकिन राजकोषिय वर्ष के मध्य तक बिजली, कोयला और रेलवे तीनों क्षेत्रों में स्पष्ट सुधार दिखाई दिया।

6. वर्ष 1980-81 के पहले महीनों में बिजली के उत्पादन की धक्का लगा क्योंकि पन-बिजली का उत्पादन बहुत कम हुआ था। यह 1979 के भयंकर सूखे का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके कारण 1980 के गर्मी के सूखे महीनों में जलाशयों में पानी का स्तर बहुत नीचा चला गया। जुलाई के बाद जब मानसून के कारण अधिकांश जलाशय फिर से भर गए तब पन-बिजली के उत्पादन में तेजी आई। तापीय बिजली के उत्पादन में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ कोयले की पूर्ति की जिन समस्याओं ने 1979 के दौरान तापीय बिजली संयंत्रों को जकड़ कर रखा था उन पर भी बहुत कुछ काम पा लिया गया और तापीय बिजली संयंत्रों को रेलों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कोयला पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। केन्द्रीय अधिकरणों की तकनीकी सलाह से, राज्यों में उन्नति और नवीकरण के कार्यक्रम शुरू करके कार्य-कुशलता में भी सुधार करने के लिए जोरदार प्रयत्न किए गए। इनके फलस्वरूप, नवम्बर और दिसम्बर 1980 में तापीय बिजली का उत्पादन, 1979 के इन्हीं महीनों की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक हो गया। पूरे वर्ष के लिए, बिजली का उत्पादन 1979-80 की अपेक्षा लगभग 6 प्रतिशत अधिक होगा। किन्तु, 1980-81 के उत्तरार्द्ध में, बिजली का उत्पादन इससे पिछले वर्ष के उत्तरार्द्ध की अपेक्षा लगभग 13 प्रतिशत अधिक होगा।

7. वर्ष 1980-81 में कोयले के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1976-77 से कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन 1060 लाख मेट्रिक टन के आस-पास रुक सा गया था। इस निराशाजनक गतिरोध को दूर कर दिया गया है और 1980-81 में कोयले और लिग्नाइट का उत्पादन 1150 लाख मेट्रिक टन से अधिक होने की आशा है। उत्पादन में सुधार होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि बिजली की उपलब्धता पहले से अच्छी रही।

8. हाल के महीनों में रेलों द्वारा माल की ढुलाई में सुधार हुआ है और पिछले तीन वर्षों में उनके कार्य-निष्पादन में जो गिरावट की स्थिति रही थी, वह अब दूर हो गई है।

9. वर्ष 1980-81 के औद्योगिक उत्पादन से यह पता चलता है कि आधारभूत ढाँचे की कठिनाइयों को दूर करने

में प्रगति हुई। मैं पहले बता चुका हूँ कि 1980-81 के पहले तीन महीनों में पन-बिजली का उत्पादन, जलाशयों में पानी का स्तर नीचा हो जाने के कारण, बहुत कम हुआ था। परिणामस्वरूप बिजली की कमी के कारण 1980-81 के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक उत्पादन काफी समय तक धीमा रहा। किन्तु वर्ष के उत्तरार्द्ध में आधारभूत ढाँचे की कठिनाइयां कम हो जाने के कारण, औद्योगिक उत्पादन में सुधार शुरू हो गया। पूरे वर्ष के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर लगभग 4 प्रतिशत रहेगी जबकि इसके विपरीत, 1979-80 में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

10. आधारभूत ढाँचे के कार्य-निष्पादन को सुधारने के प्रयत्नों के अलावा, सरकार ने औद्योगिक विस्तार की गति को तेज करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के उद्देश्य से और भी उपाय किए। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1980-81 के बजट में पूंजी-निवेश सम्बन्धी कार्य-कलाप को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए थे। उसके बावजूद जुलाई 1980 में औद्योगिक नीति का बक्तव्य दिया गया जिसमें बहुत से संवर्धनात्मक उपायों की घोषणा की गई। वर्ष के दौरान और भी कई ऐसे कदम उठाए गए जिनसे उद्योगों में अधिक पूंजी लगाई जा सके। तेल निर्यातक विकासशील देशों को कुछ चुने हुए उद्योगों के नए एककों में शेयरों के रूप में पूंजी लगाने की अनुमति देने के लिए एक नई नीति घोषित की गई। ऋणपत्र जारी करने के मार्ग-निर्देशों में संशोधन कर दिया गया ताकि पूंजी जुटाने के लिए इस साधन का अधिक प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सके।

11. हालांकि आधारभूत ढाँचे की रुकावटों के कारण 1980-81 में इन उपायों का संवर्धनात्मक प्रभाव पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सका फिर भी इन के कारण आने वाले वर्षों में दीर्घकालिक औद्योगिक विस्तार के लिए अवसर ही रास्ता साफ हो गया।

12. वर्ष 1980-81 में कृषि का उत्पादन हर तरह से संतोषजनक रहा और उससे हमारी अर्थव्यवस्था के इस अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र की बुनियादी स्वस्थता फिर से पूरी तरह सुनिश्चित हो गई। 1980-81 में मौसम की स्थिति देश के सभी भागों में तो नहीं पर अधिकांश भागों में अनुकूल रही और उसके कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जो कृषि में सुधार के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुईं। 1980-81 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन संभवतः 1320 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक होगा जो कि 1979-80 के उत्पादन से 230 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक है। यह 1978-79 में प्राप्त शिखर स्तर को भी पार कर जाएगा, हालांकि मौसम की हालत उस वर्ष की अपेक्षा कम अनुकूल थी। 1980-81 में खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ, गन्ने के उत्पादन में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ। रेशे की फसलों का उत्पादन भी अच्छा था।

13. इस उत्कृष्ट उत्पादन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि सातवें वषार के बाद वाले वर्षों में हमने जो कृषि नीति

प्रारम्भ की थी वह स्वस्थ थी। 1980-81 में इसी नीति का जोरदार तरीके से पालन किया गया। उन्नत बीजों के पर्याप्त उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त प्रयास किए गए। अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र को बढ़ा कर 480 लाख हेक्टेयर कर दिया गया जब कि 1979-80 में इनका क्षेत्र केवल 352 लाख हेक्टेयर था। घरेलू उत्पादन की अनुपूर्ति करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया। पोषक तत्वों (न्यूट्रिएन्ट्स) के रूप में उर्वरकों की खपत अनुमानतः 52.6 लाख मेट्रिक टन से बढ़ कर 56 लाख मेट्रिक टन हो गई। सिंचाई के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया और कृषि विस्तार तंत्र को भी सुदृढ़ बनाया गया ताकि प्रौद्योगिकी का अन्तरण अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो सके।

14. कृषि के उत्कृष्ट उत्पादन के साथ-साथ उद्योग में सुधार की शुरुआत हो जाने संभव है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कुल मिला कर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन मैं आगाह कर दूँ कि इससे आत्मसंतुष्ट होकर बैठ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तक जो प्रगति हुई है उसे पक्का करने की जरूरत है और यदि 1980-81 में हुए सुधार को अगले वर्ष सर्वांगीण वृद्धि में परिणत करना है तो उसमें और भी तेजी लानी होगी। इसके लिए अर्थव्यवस्था की ताकतों और कमजोरियों का यथार्थवादी मूल्यांकन करना होगा।

15. वर्ष 1980-81 के दौरान अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीतिकारी बोझ से बराबर दबा रही हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस वर्ष 1979-80 की अपेक्षा उल्लेखनीय सुधार हुआ। 1980-81 के दौरान जनवरी 1981 के अन्त तक कीमतों में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1979 के सूखे के परवर्ती प्रभावों के कारण वर्ष के पूर्वार्ध में, मुद्रास्फीतिकारी दबाव खासतौर से काफी अधिक रहे और यह बात विशेष रूप से चीनी, गुड़ और खांडसारी की कीमतों के रुझान से भी स्पष्ट होती है। वर्ष के उत्तरार्ध में पूर्ति में सुधार कर दिए जाने के फलस्वरूप स्थिति में भी निश्चित रूप से सुधार आया। अक्टूबर के मध्य से दिसम्बर के अंत तक कीमतों में गिरावट आई। तब से वे फिर बढ़ गईं। इसका एक कारण यह था कि जनवरी में पेट्रोलियम की कीमतों में अनिवार्य रूप से वृद्धि करनी पड़ी। लेकिन हाल के पिछले कुछ सप्ताहों में कीमतों की वृद्धि का स्तर सामान्य हो गया।

16. फिर भी मैं आगाह कर देना चाहूंगा कि यद्यपि मुद्रास्फीति कम हो गई है लेकिन उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अर्थव्यवस्था पर लागत वृद्धि के दबाव बराबर मौजूद हैं और खासतौर से तेल तथा अन्य आवश्यक आयातों की बढ़ती हुई कीमतों के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति देश में अपना असर दिखला रही है। चूंकि लागत वृद्धि के दबाव आगे भी बने रहेंगे इसलिए आगामी

वर्ष में लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। लागत वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए एक ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी जो कि इस समस्या को समूल हल कर सके। यह केवल मांग के प्रबंध का मामला ही नहीं है, बल्कि इसके लिए कार्यकुशलता बढ़ाने और पहले से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करने होंगे।

17. वर्ष 1980-81 में मौद्रिक और ऋण संबंधी नीतियों को मुद्रास्फीतिकारी स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया और वाणिज्यिक ऋण पर भी कड़ा नियंत्रण रखा गया। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए कि बैंक ऋण का वितरण हमारी आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण का अधिकाधिक हिस्सा कमजोर वर्गों, खासतौर से, 20 सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित वर्गों को मिले। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण का 40 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि और संबंध कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले ऋण का आधा भाग छोटे और सीमान्तिक किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को दिया जाएगा। इसके अलावा, लघु उद्योगों को दिए जाने वाले कुल ऋण का 12.5 प्रतिशत भाग देहाती कारीगरों, ग्रामीण शिल्पियों और कुटीर उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

18. देहाती क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा के विस्तार का कार्य बराबर चल रहा है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिसम्बर, 1979 के अन्त में ऐसे बैंकों की संख्या केवल 60 थी जो मार्च, 1981 के अन्त तक बढ़कर एक सौ हो जाएगी। 1981-82 में और 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाएंगे। छोटी आयोजना के अन्त तक 270 जिलों में, इनकी संख्या बढ़ाकर 170 कर देने का विचार है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी जो एक शीर्ष संस्था के रूप में ग्रामीण समुदाय की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके लिए शीघ्र ही एक विधेयक पेश किया जाएगा।

19. यह एक उपयुक्त अवसर है जब कि मैं सदन को यह बतला दूँ कि हमने जीवन बीमा निगम का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करने का निश्चय किया है ताकि वह भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम हो सके। निगम अब तक समाज को बीमा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया सेवाएं प्रदान करता रहा है। इसी प्रक्रिया में वह आकार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए यह वांछनीय हो गया है कि कार्य-कुशलता के हित में और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अवसर देने के लिए, निगम का अधिक प्रबंधनीय एककों में पुनर्गठन कर

दिया जाए। अतः हमने निगम को पांच स्वतंत्र एककों में विभाजित करने और सामान्य हित के मामलों में पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए एक समन्वयकारी निकाय स्थापित करने का निश्चय किया है। मैं समझता हूँ कि इन परिवर्तनों से निस्संदेह पालिसीधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्तर ऊँचा हो जाएगा। इस पुनर्गठन से इन संस्थाओं के कार्य में अधिक गतिशीलता आएगी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा के प्रसार में सहायता मिलेगी, जहाँ कि अब तक बहुत कम प्रगति हुई है।

20. देश की भूगतान शेष की स्थिति चिन्ता का विषय बनी हुई है। आयातित तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी सहायियों का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल संभवतः 1980-81 में 5600 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा जब कि दो वर्ष पहले यह 1677 करोड़ रुपए का था। अधिकांश वृद्धि तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है। 1980-81 में कुल आयात बिल लगभग 11,300 करोड़ रुपए का होगा जबकि निर्यातों की राशि का अनुमान केवल 7100 करोड़ रुपए का है। निवल अद्रुश्य मदों के अधिशेष की राशि को हिसाब में लेने के बाद भी, देश को 1980-81 में लगभग 2000 करोड़ रुपये के भूगतान शेष के घाटे की वित्त-व्यवस्था करनी होगी। यह राशि उपलब्ध विदेशी सहायता की राशि से बहुत अधिक है और इसलिए हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार से काफी अधिक रकम निकालनी पड़ी है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि भूगतान शेष की स्थिति को काबू में रखने के लिए एक नीति बनाई जाए। सरकार इस दिशा में अब तक कई कदम उठा चुकी है।

21. तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि आयातों पर हमारी निर्भरता को यथासंभव कम किया जा सके। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कई अग्रतटीय और तटवर्ती स्थानों पर हार्डड्रॉकाबॉन होने के प्रमाण मिले हैं और यह जरूरी है कि हम अपने सभी उपलब्ध साधनों के साथ खोज और विकास के इस कार्य में जुट जाएं। इस उद्देश्य से, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रखा गया है। समय के तकाजे को देखते हुए सरकार ने हमारे स्वदेशी सामर्थ्य के साथ-साथ विदेशी पार्टियों से भी उत्पादन विभाजन के आधार पर, ठेका किया है ताकि संभावित तेल क्षेत्रों की खोज और उनके विकास की गति को तेज किया जा सके। आशा है कि इस योजना के अन्तर्गत चुनी गई विदेशी कंपनियाँ 1981-82 के उत्तरार्द्ध में अपना काम शुरू कर देंगी।

22. भूगतान-शेष की स्थिति को देखते हुए निर्यातों को भी सबल समर्थन देने की आवश्यकता है और सरकार ने अभी हाल ही में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सम्मानित सदस्यों की याद होगा कि पिछले साल अपने

बजट भाषण में मैंने कहा था कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वित्त-व्यवस्था में सहायता देने के लिए एक निर्यात-आयात बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अब इस प्रस्ताव के ब्योरे तैयार कर लिए गए हैं और एक सांविधिक निगम के रूप में निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने के लिए चालू सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है। मैं इस प्रयोजन के लिए बजट में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूँ।

23. घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक अलौह धातुओं और तेलहनों जैसे क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार करके, आयात प्रतिस्थापन करने की भी काफी ज्यादा गुंजाइश है। इसके लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं।

24. मैं जो बजट पेश करने जा रहा हूँ उसकी नीति अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में मेरे इस मूल्यांकन पर आधारित है। हम संकट की स्थिति से बाहर निकल आए हैं जो एक साल पहले मौजूद थी। कृषि क्षेत्र में भी पूरी तरह सुधार हो गया है और अब वह लगातार वृद्धि करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन औद्योगिक स्थिति में पूरा सुधार नहीं हुआ है, परन्तु अब तक जो नीति विषयक विभिन्न कदम उठाए गए हैं उनसे औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन गई हैं। आधारभूत ढाँचे के कार्य-निष्पादन में और सुधार हो जाने पर, उद्योग के मार्ग में जो बाधाएँ हैं वे भी आगामी वर्ष में बहुत कुछ दूर हो जानी चाहिए। इसलिए 1981-82 में हमारा जोर संकट के प्रबंध से हट कर आर्थिक वृद्धि पर चला जाएगा।

25. हमें जो काम करने हैं उनके बारे में छठी आयोजना में स्पष्टतः बता दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अब इस आयोजना का अनुमोदन कर दिया है। आयोजना में प्रतिवर्ष 5.2 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सरकारी क्षेत्र में 97,500 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की जरूरत है। पहले की तरह कमजोर वर्गों के लिए विशेष बल देते हुए, कृषि के विकास को हमारी विकास नीति का केन्द्र-बिन्दु रखा गया है। लेकिन छठी आयोजना में कुछ और क्षेत्रों का भी पता लगाया गया है जो विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। बिजली, कोयला, तेल, परतन और रेलवे जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों वाली ऊर्जा-परिवहन प्रणाली के लिए भारी पूँजी-निवेश की आवश्यकता है जिससे कि ये क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के मार्ग में बाधा न बने।

26. इन विशाल और तात्कालिक कार्यों को हाथ में लेने के लिए इस बजट में ही कुछ शुरुआत करनी होगी। लेकिन यह शुरुआत इस तथ्य को भली भाँति जानते हुए करनी होगी कि मुद्रास्फीति का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए राजकोषीय घाटे को सख्त सीमाओं के भीतर रखना होगा। साथ ही, कराधान का उपयोग भी सूझ-बूझ के साथ किया जाना चाहिए जिससे कि वह

1979-80 की तरह मुद्रास्फीति की ज्वाला को और न भड़का दें।

27. राजकोषीय अनुशासन के साथ-साथ, हमें वित्तीय प्रणाली में निजी बचतों को प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा। तभी हम अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-मुद्रास्फीतिकारी वित्त व्यवस्था की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। वित्तीय प्रणाली में साधनों को प्रवाहित करने के मार्ग में दो खतरे हैं और हमें इन दोनों में निपटना होगा।

28. पहला खतरा तो यह है कि काला धन घातक रूप से बढ़ता जा रहा है। इसके कारण इस प्रकार की आमदनी पैदा होती है जो वित्तीय प्रणाली में आसानी से ऊपर नहीं आ सकती और इसलिए इसका इस्तेमाल जमाखोरी, मुनाफा-खोरी, स्ट्रेबाजी और निरर्थक उपभोग जैसे सामाजिक दृष्टि से हानिकार कार्यकलापों में किया जाता है। इससे केवल मुद्रास्फीति की आग ही भड़कती है। सरकार ने अभी हाल ही में, काली अर्थव्यवस्था में परिचालित कुछ साधनों को बाह्य बाडों की बिज्जी के जरिए, राजकोष में लेने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए व्यापक आधार पर और कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है ताकि यह सामाजिक बुराई हमारे समाज से धीरे-धीरे खत्म हो जाए।

29. वित्तीय बचतों के भाग में दूसरी बाधा यह है कि मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची है। मुद्रास्फीतिकारी स्थिति में वित्तीय बचतों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना आवश्यक हो जाता है। चूंकि वित्तीय बचतों के लिए बैंक जमा ही सबसे महत्वपूर्ण अकेला साधन है, इसलिए एक वर्ष से पांच वर्ष तक की परिपक्वता वाली जमा राशियों पर ब्याज की दर को बढ़ा देने का निश्चय किया गया है। इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा घोषणा की जा रही है। एक वर्ष से ऊपर की परिपक्वता और 2 वर्ष तक की परिपक्वता वाली जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को, जो इस समय 7 प्रतिशत है, बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। दो वर्ष से ऊपर और तीन वर्ष तक की जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को, जो इस समय 7 प्रतिशत है, बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। तीन वर्ष से ऊपर की परिपक्वता वाली जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को, जो इस समय 8.5 प्रतिशत है, बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

30. पांच वर्ष से ऊपर की जमा राशियों पर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन एक नया राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसकी परिपक्वता अवधि 6 वर्ष की होगी और जिस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। इससे लम्बी अवधि की बचतों को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

31. इन उपायों के अलावा, मैं ऋणपत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज की अधिकतम निर्धारित सीमा को, जो इस समय 12 प्रतिशत है, बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। ब्याज की अन्य दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों को देखते हुए ऐसा करना उचित है, और इससे बड़े औद्योगिक एकाई को निवेश वित्त की अपनी आवश्यकताओं को उनके अपने प्रयत्नों के जरिए जुटाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह आवश्यक है कि ये एकक, जो वित्तीय बाजार के जरिए साधन जुटाने की क्षमता रखते हैं, इस दिशा में अधिक प्रयत्नशील हों और इस प्रकार सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं के बोझ को हलका करें।

32. इस समय, पब्लिक कम्पनियां कुल मिला कर अपनी मुक्त प्रारक्षित निधि और प्रदत्त शेयर पूंजी का 25 प्रतिशत तक जनता से जमा के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। इसके अलावा उनको अपने शेयर-धारियों से अथवा कम्पनी के निवेशक द्वारा गारंटी मिलने पर दूसरे लोगों से मुक्त प्रारक्षित निधि और प्रदत्त शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत तक जमा के रूप में स्वीकार करने की भी अनुमति है। ये सीमाएं अन्तर-कम्पनी जमा राशियों के मामले में लागू नहीं होतीं। कम्पनी की जमा राशियों के मामले में लागू होने वाले ये उपबन्ध भागों भी लागू रहेंगे। किन्तु इन जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज के संबंध में 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू करने का प्रस्ताव है। इन निर्णयों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं।

33. उद्योग में पूंजी-निवेश को सुविधा प्रदान करने के एक और कदम के रूप में, हमने शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) के मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत इस अपेक्षा में ढील देने का निश्चय किया है कि प्रवर्तक (प्रमोटर) नई कम्पनी की इक्विटी का अधिक से अधिक 40 प्रतिशत अंश ही धारण कर सकते हैं। यह व्यवस्था कुछ मामलों में वित्तीय संस्थाओं की इस अपेक्षा से मेल नहीं खाती कि प्रवर्तक परियोजना की कुल लागत का एक न्यूनतम प्रतिशत भाग खुद लगाए। दो भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं के बीच विद्यमान इस भारी विरोध के कारण नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी कठिनाइयां उपस्थित होती थीं। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रवर्तकों को परियोजना की प्रारंभिक अवस्थाओं में, 40 प्रतिशत की सीमा से ऊपर इक्विटी रखने की अनुमति दी जाएगी। किन्तु 40 प्रतिशत के ऊपर की इक्विटी धारिता को, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, आम जनता को बिज्जी की पेशकश के द्वारा छोड़ना होगा। युक्तिसंगत बनाने के इस कार्य से उद्योग में नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आनी चाहिए।

34. मुझे विश्वास है कि इन व्यापक उपायों से वित्तीय प्रणाली में बचतों को प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक निवेश के लिए धनराशियों की उपलब्धता बढ़ेगी। इनसे आगामी वर्ष में वृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी।

35. बजट तैयार करने में मैंने मोटे तौर पर जो दृष्टिकोण अपनाया है उसकी ओर कुछ सम्बद्ध नीति विषयक नए कार्यों की रूपरेखा बतलाने के बाद, अब मैं 1980-81 के संशोधित अनुमानों और 1981-82 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ।

1980-81 के संशोधित अनुमान

36. वर्ष 1980-81 के बजट अनुमानों में 1445 करोड़ रुपए के घाटे की परिकल्पना की गई थी। किन्तु राज्यों और योजना आयोग के बीच विचार विमर्श के परिणामस्वरूप, कई मामलों में राज्यों की आयोजनाओं के परिचय में वृद्धि कर दी गई। राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि में 310 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी गई। हमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भी 58 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देनी पड़ी। कृषि में काम आने वाली वस्तुओं (इनपुट्स) की पूर्ति के लिए राज्यों की अल्पकालिक उधार दिए जाने की व्यवस्था में भी 25 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी।

37. इसके अलावा, राज्यों को बाढ़ राहत कार्य में मदद देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 90 करोड़ रुपए की सहायता दी है। आसाम सहित कुछ उत्तरपूर्वी राज्यों को 76 करोड़ रुपए की विशेष उधार सहायता दी गई है ताकि वे विशेष कठिनाइयों के कारण अपने साधनों में रही कमी को पूरा कर सकें।

38. आर्थिक सहायताओं के लिए भी मूल व्यवस्था से अधिक राशि दी जा रही है। आयातित उर्वरकों पर होने वाले निवल व्यय के लिए की गई व्यवस्था में 104 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता कंट्रोल के कपड़े पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता और नकद प्रतिकर सहायता तथा निर्यात के लिए बाजार विकास व्यवस्था में भी 110 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है।

39. रक्षा व्यय की व्यवस्था में भी 200 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी है।

40. सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना बजट के समय प्रत्याशित किया गया था। इसलिए इन उपक्रमों को 104 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजना-भिन्न सहायता देना आवश्यक हो गया है।

41. जहां तक केन्द्रीय आयोजना के व्यय का संबंध है, मुझे सदन को यह बताना है कि विजयी, कांयला और पेट्रोलियम जैसे अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों का व्यय संतोषजनक रहा है। सदन को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संवितरणों का स्तर प्रारम्भिक बजट अनुमानों से कहीं अधिक रहा है। इसलिए मैं निगम के लिए 126 करोड़ रुपए की और रकम की

व्यवस्था कर रहा हूँ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए 50 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की जा रही है ताकि यह बैंक अपनी बढ़ती हुई वचनबद्धताओं को पूरा कर सके। इस्पात और नागर विमानन जैसे कतिपय क्षेत्रों में, आंतरिक साधन जुटाने में कमी रही है और इसलिए इनकी आयोजनाओं के लिए बजट में काफी अधिक रकम की व्यवस्था करनी पड़ी है। कुछ क्षेत्रों के आयोजना-व्यय में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन इन्हें हिसाब में लेने के बाद भी संशोधित अनुमानों में 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट में की गई व्यवस्था की राशि 297 करोड़ रुपए अधिक होगी।

42. अब केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का अनुमान 22808 करोड़ रुपए का है जबकि इसकी तुलना में बजट में 21467 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

43. जहां तक प्राप्तियों का संबंध है, मुझे सदन को यह बतलाने का प्रसन्नता हो रही है कि 1980-81 के बजट में आय-कर में दी गई रियायतों के बावजूद, कर-राजस्वों की कोई हानि नहीं हुई है। मेरी यह धारणा सही निकली कि कराधान की दर कम होने से लोग करों के नियमों का स्वेच्छा से अधिक पालन करते हैं। अब निगम-कर से प्राप्तियों की राशि 1515 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 35 करोड़ रुपए अधिक होगी। संघ उत्पाद शुल्कों की प्राप्तियां भी 6265 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 99 करोड़ रुपए अधिक होंगी। अधिक आयात किए जाने और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें ऊंची हो जाने के कारण चालू वर्ष में सीमा-शुल्क प्राप्तियों की राशि 2989 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 361 करोड़ रुपए अधिक होगी। विभिन्न करों में राज्यों के हिस्से की राशि घटाने के बाद, अब केन्द्र का निवल राजस्व 8922 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 419 करोड़ रुपए अधिक होगा।

44. पूंजी प्राप्तियों में भी 7694 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 245 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। यह वृद्धि 104 करोड़ रुपए के अधिक बाजार ऋणों और विशेष बाह्य बांडों की बिक्री से 200 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों के कारण होगी जो अत्यंत होने वाली कुछ कमियों के परिणामस्वरूप कुछ हद तक कम हो जाएगी।

45. अब 20833 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जब कि बजट में 20022 करोड़ रुपए की राशि आंकी गई थी। आशा है कि चालू वर्ष का घाटा अब लगभग 1975 करोड़ रुपए का होगा। सदन को यह मालूम हो कि बजट के घाटे की लगभग सारी की सारी वृद्धि का कारण यह है कि राज्यों और केन्द्र की आयोजनाओं के लिए बजट में पहले से अधिक रकम की व्यवस्था की गई है।

1981-82 के बजट अनुमान

46. वर्ष 1981-82 का बजट छठी आयोजना के उद्देश्यों, उसकी प्राथमिकताओं तथा उसके कार्यक्रमों को प्रतिबिंबित

करता है। 1981-82 में केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आयोजना परिषदों के लिए 17479 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, जबकि इसकी तुलना में 1980-81 के बजट अनुमानों में 14593 करोड़ रुपए रखे गए थे। इससे लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। 1981-82 के लिए केन्द्र के आयोजना-परिषद में 1980-81 के 7340 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में काफी अधिक वृद्धि की जा रही है और इसे 8619 करोड़ रुपए किया जा रहा है, अर्थात् इसमें 17.4 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। इस राशि का वित्तपोषण 6309 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था द्वारा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 2310 करोड़ रुपए के बजट-भिन्न साधनों द्वारा किया जाएगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल अनुमोदित आयोजना परिषद 8860 करोड़ रुपए का होगा जबकि 1980-81 के बजट अनुमानों में इसकी राशि 7253 करोड़ रुपए की थी, अर्थात् इस में 22 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के आस्ते केन्द्रीय सहायता के लिए 3462 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

47. हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बहुत प्रभावशाली है और कृषि के विकास की गति समूची अर्थ-व्यवस्था की गति का निर्धारण करती है, केन्द्र और राज्यों की वार्षिक आयोजनाओं में कृषि पर किए जाने वाले परिषद की राशि को, 1980-81 के 925 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, बढ़ाकर 1047 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि एकमात्र ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे कृषि को उच्च उत्पादकता वाली वैज्ञानिक कृषि के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तदनुसार 1981-82 में 25 लाख हेक्टेयर और जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 1981-82 के लिए केन्द्र और राज्य की वार्षिक आयोजना में बड़ी और मध्यम सिंचाई के परिषद को काफी ज्यादा बढ़ाकर 1408 करोड़ रुपए किया जा रहा है जब कि 1980-81 के बजट अनुमानों में इसकी राशि 1213 करोड़ रुपए की थी। छोटी सिंचाई का परिषद, 1980-81 के 266 करोड़ रुपए की तुलना में 301 करोड़ रुपए होगा।

48. कृषि के कुल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के साथ-साथ, भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्तिक किसानों, ग्रामीण कारीगरों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों जैसे ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के विशेष कार्यक्रमों पर वार्षिक आयोजना में बहुत जोर दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं उनमें से एक है: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। हम इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आयोजना में 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं और इतनी ही राशि की व्यवस्था राज्यों द्वारा भी की जाएगी।

49. कमजोर वर्गों को सहायता देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कुछ अनुपूरक और कभी-कभी एक जैसे कई कार्यक्रमों को भी शामिल कर लिया गया है जो जनता के कुछ विशेष वर्गों के लिए पहले बालू किए गए थे। हम ने इस कार्यक्रम के लिए और महत्वपूर्ण विकास तथा सूखा-प्राणिकित क्षेत्रों के कार्यक्रमों जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए 198 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। राज्यों से बराबर का अनुदान प्राप्त हो जाने पर, आशा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिये 1981-82 में 30 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आने में सहायता मिलेगी।

50. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजनाओं के हेतु केन्द्रीय सहायता देने का कार्यक्रम वर्तमान सरकार ने अपने पहले बजट में ही शुरू कर दिया था। अगले साल के लिए हमने 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके अलावा राज्यों के अनुसूचित जाति विकास निगमों में 13 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे और इतनी ही राशि राज्यों द्वारा भी लगाई जाएगी; इससे निगमों को वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में धनराशि जुटाने में सहायता मिलेगी। जनजातीय उप-आयोजना, जो कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास का एक माध्यम है, के लिए 1981-82 में 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है जो कि 1980-81 के 70 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है। विशेष पहाड़ी विकास कार्यक्रम के लिए, 1980-81 के 61 करोड़ रुपए की तुलना में, 92 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

51. समस्याग्रस्त गांवों में पीने के निरापद जल की जल्दी में व्यवस्था करने की सरकारी नीति के अनुसार, 1981-82 में 110 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। राज्यों की आयोजनाओं में की गई व्यवस्थाओं को साथ मिलाने पर अगले वर्ष इस योजना के अन्तर्गत लगभग 36000 और गांव शामिल कर लिए जाएंगे।

52. वार्षिक आयोजना में तेल, कोयला और बिजली जैसे क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 1981-82 में कोयले और लिग्नाइट की परियोजनाओं के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार इस में 1980-81 के 443 करोड़ रुपए से 31 प्रतिशत अधिक राशि की व्यवस्था की गई है।

53. केन्द्रीय आयोजना में बिजली के परिषद में भी भारी वृद्धि की गई है। 1981-82 में हमने, पिछले बजट के 520 करोड़ रुपए की तुलना में 721 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इससे बिजली के क्षेत्र में केन्द्र की बढ़ती हुई भूमिका का पता चलता है। हम प्रस्ताव करते हैं कि जम्मू और कश्मीर की दुलहस्ती परियोजनाओं को और बिहार की कोइलकारो परियोजनाओं को अगले वर्ष केन्द्रीय

क्षेत्र में ले लिया जाए। बिजली के क्षेत्र के लिए राज्यों और केन्द्र की आयोजनाओं में कुल मिलाकर 3326 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि 1980-81 में इसकी राशि 2745 करोड़ रुपए की थी। आशा है कि 1981-82 में 3000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चालू हो जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण वर्ष में 22000 गांवों में बिजली पहुंचाने और 4.25 लाख पम्प सेटों को बिजली देने की व्यवस्था है।

54. तेल और प्राकृतिक गैस के साधनों की खोज और विकास को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है उसे देखते हुए, पेट्रोलियम के क्षेत्र के लिए 1981-82 में आयोजना परियोजना को बढ़ाकर 1011 करोड़ रुपए कर दिया गया है जब कि चालू वर्ष में 780 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में 67 करोड़ रुपए के परियोजना का प्रस्ताव है।

55. इस्पात के लिए 1981-82 में 796 करोड़ रुपए के परियोजना की व्यवस्था की जा रही है। इस क्षेत्र की एक उल्लेखनीय घटना यह है कि कोठागुडम में हाल ही में स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए प्रदर्शन संयंत्र (डिमोन्स्ट्रेशन प्लांट) को चालू कर दिया गया है। यह परियोजना भारत के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि गैर-कोकिंग कोयले का इस्तेमाल करके स्पंज लोहे का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी से, हमें देश में कोकिंग कोयले के सीमित भंडारों के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी।

56. वर्ष 1981-82 की वार्षिक आयोजना में खनिज विकास के लिए 1980-81 के 130 करोड़ रुपए के मुकाबले 223 करोड़ रुपए के काफी ऊंचे परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में उड़ीसा एल्यूमिनियम परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है; यह परियोजना राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी नामक नई पंजीकृत कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जिस का मुख्यालय उड़ीसा के भुवनेश्वर नगर में होगा। परियोजना की अधिकांश लागत की वित्त-व्यवस्था विदेशी ऋण और वाणिज्यिक उधारों से हो जाने की आशा है।

57. परिवहन की सुविधाओं में सुधार करने के लिए हमारी जिन्ता के अनुरूप ही, हम ने परिवहन क्षेत्र के परियोजना को 1980-81 के 1351 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1535 करोड़ रुपए कर दिया है। सम्मानित सदस्यों को पहले ही मालूम हो चुका है कि रेलवे के आयोजना परियोजना को 1980-81 के 760 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा बढ़ाकर 980 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पत्तनों के विकास के लिए 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें कांडला, मुक्तिबुड़ और विशाखापत्तनम् में अतिरिक्त बर्थों का निर्माण शामिल है।

58. संचार की सुविधाओं में सुधार करने और उन्हें आधुनिक बनाने के हमारे अभियान के अनुरूप, 1981-82

में 2 लाख सीधे टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। संचार सहित डाक और तार के लिए आयोजना में 518 करोड़ रुपए के परियोजना की व्यवस्था की गई है।

59. रसायनों और उर्वरकों के लिए 390 करोड़ रुपए के परियोजना की व्यवस्था की जा रही है जिस में काफी बड़ी राशि थाप वैशेट, हजीरा और नामरूप स्थित गैस-आधारित उर्वरक परियोजनाओं के लिए रखी गई है। नए नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरक संयंत्रों के लिए भी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

60. ग्रामीण और लघु उद्योगों में, ग्रामीण कारीगरों और शिल्पियों के परंपरागत कला-कौशल को जीवित रखने के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने की भी अत्यधिक क्षमता है। इन क्षेत्रों के लिए 162 करोड़ रुपए का परियोजना निर्धारित किया गया है; इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में भी इन क्षेत्रों के लिए 153 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

61. अन्त में, मैं जनसंख्या वृद्धि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। गरीबी हटाने के हमारे सभी प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे, यदि हम जनसंख्या वृद्धि की दर को कम नहीं कर सकेंगे। हमने परिवार कल्याण कार्यक्रम में नए प्राण फूंकने का काम सच्चे मन से हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम के लिए 1981-82 में 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

62. सरकार इस बात से बहुत चिन्तित है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त संचार सुविधाओं का अभाव है। इसलिए हमने छः राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम हाथ में लेने का निश्चय किया है जिनकी कुल लंबाई 1700 किलोमीटर होगी और जिन पर कुल मिला कर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह भी निश्चय किया गया है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 36 पर नौगांव से डीमापुर को अधिक सीधे रास्ते से जोड़ा जाए जिस पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मेघालय में भारत बंगला देश सीमा के साथ-साथ बनी हुए सड़क के कुछ बाकी रहे टुकड़ों को बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में रेल की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। सम्मानित सदस्यों को मालूम ही है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तृतीय स्तर की हवाई सेवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है।

63. आयोजना-भिन्न व्यय को भी न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल की गई है। रक्षा व्यय चालू वर्ष के 3800 करोड़ रुपए के मुकाबले 4200 करोड़ रुपए का होगा। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात में भ्रम से सहमत होगा कि इस कठिन समय में रक्षा की मुक्तियुक्त आवश्यकताओं को भली भांति पूरा किया जाना चाहिए।

64. व्याज की अदायगियों के लिए चालू वर्ष के 2665 करोड़ रुपए के मुकाबले 3124 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, यह वृद्धि मुख्य रूप से आन्तरिक कर्ज के कारण हुई है। नेप्था और अन्य निवेश्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण स्वदेशी उर्वरकों के उत्पादन की लागत में भी बढ़ोतरी हो गई है। आयातित उर्वरकों की लागत भी बढ़ गई है। इसलिए, 1981-82 के बजट में उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए 679 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो चालू वर्ष में की गई 466 करोड़ रुपए की व्यवस्था से काफी अधिक है।

65. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आयोजना-भिन्न उधारों की व्यवस्था को चालू वर्ष के 454 करोड़ रुपए से घटाकर 318 करोड़ रुपए कर दिया गया है क्योंकि अगले वर्ष में उनके कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भी अगले वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपए को एकमुश्त व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में पेंशन भोगियों को महंगाई राहत, जो इस समय उपभोक्ता कीमतों के सूचक अंक में प्रत्येक 16 बिन्दु की वृद्धि के पीछे पेंशन की राशि के 5 प्रतिशत के हिसाब से मिलती है इसकी बजाय, प्रत्येक 8 बिन्दु के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से मिला करेगी। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। इन परिवर्तनों से पेंशन भोगियों द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी।

66. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि भारत को 1982 में अगले एशियाई खेल राजधानी में आयोजित करने का सुअवसर मिल रहा है। इसलिए इन खेलों के लिए अगले वर्ष आवश्यक व्यय की व्यवस्था संबंधित मंत्रालयों के बजटों में की जा रही है। इसमें से अधिकांश व्यय सड़कों, स्टेडियमों और खेल-कूद की अन्य सुविधाओं जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों के सुधार और निर्माण पर होगा।

67. अनुमान है कि 1981-82 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय, चालू वर्ष के 13736 करोड़ रुपए की तुलना में, 15100 करोड़ रुपए होगा।

68. जहां तक 1981-82 में होने वाली प्राप्तियों का संबंध है, अनुमान है कि कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर-राजस्व 14472 करोड़ रुपए प्राप्त होगा, इस प्रकार इसमें चालू वर्ष के 13133 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1339 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। 1981-82 में करों में राज्यों का हिस्सा अनुमानित: 4206 करोड़ रुपए होगा जबकि चालू वर्ष में इसकी राशि 3792 करोड़ रुपए की थी। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र का निवल कर-राजस्व, चालू वर्ष के 9341 करोड़ रुपए के मुकाबले 10266 करोड़ रुपए होगा।

69. अनुमान है कि बाजार उधारों के रूप में 2800 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जब कि चालू वर्ष में 2604 करोड़ 1399 GI/80—2

रुपए प्राप्त हुए थे। अल्प वृत्तों से चालू वर्ष के 1100 करोड़ रुपए की तुलना में, अगले वर्ष 1250 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। उधारों की वापसी-अदायगियों को निकाल कर निवल विदेशी सहायता अनुमानित: 1379 करोड़ रुपए की मिलेगी जबकि चालू वर्ष में इसकी राशि 1258 करोड़ रुपए की थी। विशेष बाह्य बांडों की बिक्री से अगले वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ रुपए की प्राप्ति को भी हिसाब में लिया गया है।

70. रेलवे के यात्री-किराए और माल-भाड़े में प्रस्तावित परिवर्तनों, डाक-तार की शुल्क-दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों, जिन का उल्लेख मैं कुछ बाद में करूंगा और अनिवार्य निक्षेप (आय-करदाता) योजना को 31-3-1981 के बाद भी लागू रखने के प्रभावों को हिसाब में लेने के बाद 1981-82 में कुल प्राप्तियों अनुमानित: 23061 करोड़ रुपए की होंगी और कुल व्यय 24871 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार कराधान की मौजूदा दरों पर बजट में कुल मिला कर 1810 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

भाग-ख

71. आय-कर और अन्य प्रत्यक्ष कर, साधन जुटाने और विपमताओं को कम करने के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं हम इन उद्देश्यों को करों की दरें बढ़ाकर प्राप्त करने की बजाय कर-दंडों में मौजूद कानूनी खामियों को दूर करके और प्रशासन को प्रभावोत्पादक बना कर प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि करों की दरें बढ़ाने से तो प्रायः कर-अपवर्धन और इस के साथ-साथ काले धन को बढ़ावा मिलता है? मेरे प्रस्ताव आज के कठिन समय में मध्यम वर्गों को राहत देने की हमारी पार्टी की स्वीकृत नीति को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

72. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष व्यक्तिगत आयों पर आय-कर की छूट की सीमा 12,000 रुपए तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन शून्य खण्ड दर 8,000 रुपए पर ही रखी गई थी। मदन को मेरे प्रस्ताव से प्रसन्नता होगी कि पंजीकृत फर्मों और छूट की सीमा से ऊपर की अलग आय वाले एक या एक से अधिक सदस्यों वाले हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों से भिन्न गैर-निगमित करदाताओं के मामले में छूट की सीमा को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया जाए: मध्यम आय वर्गों को पर्याप्त राहत देने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि शून्य दर खण्ड को 8,000 रुपए से बढ़ा कर 15,000 रुपए कर दिया जाए और 30,000 रुपए तक दर अनुसूची का फिर से गठन किया जाए। 15,001 रुपए से 25,000 रुपए तक के खण्ड पर आय-कर की दर 30 प्रतिशत और 25,001 रुपए से 30,000 रुपए तक के खण्ड पर 34 प्रतिशत होगी। इससे ऊपर के खण्डों पर आय कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लगभग 14 लाख करदाता आयकर के जाल से निकल जाएंगे। मैं

यह दावा करने का साहस कर सकता है कि इस से पहले कभी भी एक ही बार में इतने अधिक लोगों को आय-कर के भार से मुक्ति नहीं दी गई। इसके अलावा, 15,001 रुपए से 30,000 रुपए तक के आय समूहों के 11.5 लाख और करदाताओं को भी अलग-अलग मात्रा में राहत मिलेगी। 15,000 रुपए के आय-स्तर पर करदायित्व में 990 रुपए, 20,000 रुपए पर 495 रुपए और 25,000 रुपए पर 220 रुपए की कमी हो जाएगी। लेकिन 30,000 रुपए से अधिक की आय वाले कर-दाताओं के मामले में करदायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार मैंने एक वर्ष में देश के लगभग 40 लाख आय करदाताओं में से 25 लाख से अधिक आय-करदाताओं को या तो आय-कर से पूरी छूट दे दी है या उनका कर-दायित्व कम कर दिया है।

73. इस समय, वेतन भोगी करदाता 10,000 रुपए तक वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर और गैर वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर लेकिन कुल मिलाकर 3,500 रुपए की अधिकतम सीमा के अन्दर-अन्दर मानक कटौती के हकदार हैं। ये सीमाएं 1974 में निर्धारित की गई थीं। वाद के वर्षों में कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए और वेतन भोगी करदाताओं को राहत देने के एक माध्यम के रूप में मैं मानक कटौती को 5,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। सम्मानित सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि यह लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। इस समय, सवारी भत्ता पाने वाले कर्मचारी केवल 1,000 रुपए तक की मानक कटौती के हकदार हैं। अब यह प्रस्ताव है कि उन्हें पूरी मानक कटौती का लाभ प्रदान किया जाए।

74. अर्थव्यवस्था में बचतों के स्तर को बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए, मैं आय-करदाताओं के लिए अनिवार्य जमा योजना को और दो वर्षों के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

75. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में निगम क्षेत्र की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी अपने भाषण में उद्योगों में पूंजी लगाने के वातावरण को सुधारने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया है। अब मैं सभी श्रेणियों की कंपनियों द्वारा देय आय-कर अधिभार को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने अर्थात् इसमें 5 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका परिणाम यह होगा कि निगम क्षेत्र में धनराशि की आन्तरिक उपलब्धता बढ़ जाएगी और उनके अपने साधनों से पूंजी निवेश का वित्तपोषण करने का क्षेत्र बड़ जाएगा। इस कदम से उन उपायों के प्रभाव को और बल मिलेगा जिनका मैं ने औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय साधन जुटाने के वास्ते पहले जिक्र किया है।

76. जैसाकि सम्मानित सदस्य जानते हैं, सभी श्रेणियों के करदाताओं को "जैसे आप-कमाएं-वैसे-ही-अदायगी-करें" के आधार पर कर की अग्रिम अदायगी करनी होती है। लेकिन

कंपनियों द्वारा अतिवार की अदायगी अग्रिम नहीं की जाती मैं इस विमंगति को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव करता हूँ कि अतिकर की राशि भी सुमंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अग्रिम अदा की जाए।

77. आय-कर-अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में उन उद्योगों की एक सूची दी गई है जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट निवेश सम्बन्धी कर रियायतों के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, इन उद्योगों के सम्बन्ध में तब तक निवेश छूट या कर अवकाश नहीं मिलता जब तक कि वे लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योग न हों। शुरू में, इस अनुसूची में सम्मिलित उद्योगों को निम्न प्राथमिकता वाले उद्योग माना जाता था। लेकिन, इस सूची को समीक्षा करने पर मुझे इन सूची-बद्ध उद्योगों में से कई उद्योगों को निम्न प्राथमिकता वाले उद्योग मानने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। अतः उद्योगों के 14 समूहों को इस अनुसूची में से निकाल दिया जाएगा और वे अब विनिर्दिष्ट कर रियायतों के पात्र बन जाएंगे। इन उद्योगों में बिजली के पंखे, प्रेशर कुकर, कांच और कांच का सामान, वर्णक, रंग, पेंट, इनेमल, वार्निश, कालिख और मेल्यूलोसी लेकर, स्टीन के बर्तन और पॉसिलिन का सामान, मोजेक हाइल और कांचित टाइल, संश्लिष्ट डिजेंट, ध्वनिवर्धक (एम्प्लीफायर) या जनता को सम्बोधन करने के लिए कोई और साधन, वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम पात्र के उद्योग शामिल हैं। ये उद्योग, जिनमें से कुछ एक में निर्गत की क्षमता है, अब विनिर्दिष्ट रियायतों के पात्र बन जाएंगे।

78. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने पिछले वर्ष करों से बचने के एक उपाय के रूप में निजी वैवैकिक न्यासों (प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट) के इस्तेमाल को रोकने के लिए कई उपाय किए थे। कर से बचने का एक और तरीका सरकार के ध्यान में आया है और वह है मौखिक न्यासों (ओरल ट्रस्ट) की स्थापना। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए मेरा प्रस्ताव मौखिक न्यासों को आय-कर और धन-कर की परिधि में ले आने का है। इन न्यासों पर अधिकतम सीमांत दर से आयकर लगेगा और धन-कर 3 प्रतिशत की समान दर या किसी व्यक्ति के मामले में लागू उचित दर, इनमें से राजस्व की दृष्टि से जो भी लाभप्रद हो, उस दर से लगेगा। यह प्रस्ताव निर्धारण वर्ष 1981-82 में लागू हो जाएगा।

79. उचित कर-दायित्व से बचने की जो एक और तरीका काम में लाई जा रही है वह है: सदस्यों के श्रेणियों की परिभाषा किए बिना व्यक्तियों के संगमों (एसोसिएशन) की स्थापना। इस प्रकार एक बड़ी संख्या में ऐसी कर-योग्य इकाइयां बन जाती हैं जिन पर वर्तमान कानून के अन्तर्गत अलग-अलग आयकर लगता है। अब मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि व्यक्तियों के ऐसे संगमों पर अधिकतम सीमांत दर से आयकर और 3 प्रतिशत की दर या व्यक्ति के मामले में लागू उचित दर, इन दोनों में जो भी ऊँची हो, उस दर

से धन-कर लगाया जाए। यह प्रस्ताव भी निर्धारण वर्ष 1981-82 से लागू हो जाएगा।

80. अपने भाषण में मैंने पहले तेल की खोज और तेल के उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की भागीदारी का जिक्र किया है। इस सम्बंध में करों के मामले में कई उपाय करने जरूरी हैं। पहली बात यह है कि आय-कर अधिनियम और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम को अपतटीय क्षेत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव है। दूसरे, आय-कर अधिनियम और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में कुछ उपयुक्त उपबंध जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ खनिज तेलों और गैस के व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग के पक्ष में आय-कर या अतिकर के सम्बंध में कोई, छूट देने, कर की दर में कमी करने या उसमें कोई और संशोधन करने की व्यवस्था कर सकेगी। नए उपबंधों के अधीन जब अधिसूचनाएं तैयार हो जाएंगी तब उन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया जाएगा। ऐसा भी प्रस्ताव है कि खनिज तेलों की खोज करने या उन्हें निकालने या उनका उत्पादन करने के कारबार के मामले में कटौती की विशेष व्यवस्था में सम्बंधित आयकर अधिनियम की धारा 42 में संशोधन कर दिया जाए ताकि उसके क्षेत्र का विस्तार किया जा सके और उसके अन्तर्गत वे मामले भी आ जाएं जिनमें ऐसे व्यवसाय में केन्द्रीय सरकार स्वयं भागीदार न हो लेकिन अपने प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती हो।

81. यद्यपि तेल की अनिरिक्त मात्राओं की खोज बिना किसी रुकावट के, जोर-शोर से बराबर जारी रहनी चाहिए लेकिन नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को तेज करने और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तरकास आवश्यकता है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा जिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को वाणिज्यिक स्तर तक ले आया गया है, उन में सौर ऊर्जा जीवभार (बायोमास) ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल है। ऊर्जा के इन गैर परम्परागत स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ राजकोषीय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अतः नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों और प्रणालियों के निर्माण के लिए स्थापित मशीनरी और संयंत्र पर, इस समय जो 10 प्रतिशत की मूल्यह्रास-छूट उपलब्ध है उसे मैं 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। व्यापार व्यवसाय में उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा के ऐसे स्रोतों तथा प्रणालियों पर भी बड़ी दर पर मूल्यह्रास-छूट दी जाएगी। इस सम्बंध में सरकार द्वारा जिन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है, उन में विनीय संस्थाओं से उचित शर्तों पर सम्बन्ध उद्योगों के लिए उधार की व्यवस्था करना और कतिपय करों तथा शुल्कों में छूट देना शामिल है।

82. मैंने अपने भाषण में पहले हमारी भुगतान शेष सम्बन्धी कठिन स्थिति को देखते हुए निर्यातों का बढ़ावा देने की अनिवार्य आवश्यकता का जिक्र किया था। मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यात प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सरकार का यह प्रस्ताव है कि इन क्षेत्रों में स्थापित किए गए एककों को अन्य रियायतों के बदले शुरू के पांच वर्षों तक पूरा कर-अवकाश दे दिया जाए।

83. चाय हमारा एक महत्वपूर्ण निर्यात-प्रधान उद्योग है। इस समय, चाय के व्यापार की आमदनी का हिसाब लगाते हुए किसी नए क्षेत्र में या पहले से परित्यक्त किसी भूमि पर चाय की झाड़ियां लगाने के व्यय के 50 प्रतिशत के बराबर विकास छूट दी जानी है। इस प्रयोजन के लिए विकास छूट के पात्र व्यय की राशि पहाड़ी इलाकों में स्थित भूमि के मामले में 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक और आम क्षेत्रों के मामले में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित है। हाल के वर्षों में झाड़ियों के लगाने की लागत में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि ये अधि-कतम सीमाएं दार्जीलिंग स्थित भूमि के लिए 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अन्य पहाड़ी इलाकों में स्थित भूमि के लिए 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और मैदानों में स्थित भूमि के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी जाएं।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 35 ख के अन्तर्गत घरेलू कम्पनियां और भारत में निवासी निगम-भित्र कर-दाता, कर-योग्य लाभों का हिसाब लगाते समय, उनके द्वारा विकसित निर्यात बाजारों पर किए गए अहित व्यय के एक सही एक बटा तीन की दर से आनुपातिक कटौती के हकदार होते हैं। पिछले वर्ष इस व्यवस्था के क्षेत्र को कम कर दिया गया था, क्योंकि इसका उन कार्यों पर भारत में किए गए ऐसे व्यय के बारे में आनुपातिक कटौती के लिए दावा करने के वास्ते दुरुपयोग किया गया, जिनका निर्यात बाजारों का विकास करने के बूनियादी उद्देश्य के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। ऐसे दुरुपयोग से बौकस रहने के लिए और साथ ही निर्यात बाजार के विकास के लिए किए जाने वाले सभी वैध प्रयासों की रक्षा करने के प्रयोजनों से सरकार ऐसे नियम बना रही है जिनमें कई एक विशिष्ट कार्यकलापों का ब्योरा दिया गया होगा जिन्हें धारा 35 ख के अन्तर्गत छूट दी जाएगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।

85. इलेक्ट्रानिकी एक श्रम प्रधान और निर्यात प्रधान उद्योग है। इसलिए मैं इलेक्ट्रानिक संघटक उद्योग को आयकर अधिनियम की नवी अनुसूची में शामिल करने और यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि इलेक्ट्रानिक संघटकों के निर्माण में अन्य रूप से लगी हुई किसी भारतीय कम्पनी ने किसी घरेलू कम्पनी द्वारा अजिन लाभांश पूर्ण रूप से आय-कर मुक्त हो।

86. आयकर अधिनियम के अधीन लघु उद्योग उपक्रमों को करसम्बन्धी कुछ रियायतें मिलती हैं। इस प्रयोजन के लिए, किसी औद्योगिक उपक्रम को एक लघु उद्योग उपक्रम तब माना जाता है जब उस उद्योग में स्थापित मशीनरी और संयंत्र का मूल्य पिछले वर्ष के अन्तिम दिन 10 लाख रुपये से अधिक न हो। मैं अब लघु उद्योग की नई परिभाषा के अनुरूप इस सीमा को बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।

87. वर्तमान कानून के अधीन पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय को कर-योग्य आय का हिसाब लगाने समय अर्जित मुनाफे (प्रोफिट) और लाभ (गेन) के 20 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती की जाती है। मैं इस रियायत को 1981-82 के निर्धारण वर्ष से पांच वर्ष के लिए आगे जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

88. इस समय अनुमोदित वित्तीय निगमों और सार्वजनिक आवास वित्त कम्पनियों को कुछ शर्तों के अधीन, अपनी आमदनी के एक विशिष्ट प्रतिशत को विशेष प्रारक्षित निधि में ले जाने के सम्बन्ध में कटौती का हक प्राप्त है। लेकिन ऐसी कटौती की समग्र पात्र राशि, कुल मिलाकर, प्रदत्त शेरर पूंजी की राशि के बराबर अधिकतम सीमा (सीलिंग) तक होती है। ऐसे निगमों और ऐसी कम्पनियों को इस प्रकार अपनी प्रारक्षित निधियों का निर्माण करने के योग्य बनाने के लिए मैं वर्तमान अधिकतम सीमा को दुगुना करने का प्रस्ताव करता हूँ।

89. मौजूदा कानून के अधीन, निवासी व्यक्ति और अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग अपने आश्रितों की शिक्षा के सम्बन्ध में कटौती के हकदार है। मैं ऐसे आश्रित के मामले में, जो सुसंगत लेखा वर्ष में 182 या उससे अधिक दिनों तक इलाज के लिए अस्पताल में रहा हो, कटौती की इस रकम को दुगुना करके 4,800 रुपये कर देने और अन्य मामलों में 1,200 रुपये कर देने का प्रस्ताव करता हूँ। निस्सन्देह, अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में सदन द्वारा इस रियायत का स्वागत किया जाएगा।

90. मैं सम्पदा-शुल्क अधिनियम के अधीन कुछ उल्लेखनीय रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूँ। सम्पदा-शुल्क को 50,000 रुपये की वर्तमान सीमा 1958 में निर्धारित की गई थी। मैं इसे बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये अर्थात् उतनी ही कर देने का प्रस्ताव करता हूँ जितनी कि धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत है। मैं यह व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पदा-शुल्क के प्रयोजन के लिए एक रिहायशी मकान या उसके किसी हिस्से का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाएगा जैसा कि धन-कर के प्रयोजन के लिए किया जाता है। चूंकि सम्पदा-शुल्क अधिनियम में केवल राज्यों के विधान मण्डलों की सहमति से संशोधन किया जा सकता है इसलिए इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए बाद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

91. मैं आयकर अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति की अर्हताओं को ऊंचा करने के लिए आयकर अधिनियम में कुछ संशोधन करना चाहता हूँ।

92. प्रत्यक्ष कर कानूनों में किए जाने वाले अन्य संशोधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं यहां उन संशोधनों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कर सदन का समय नहीं लेना चाहता।

93. व्यक्तिगत आमदनियों पर आयकर की दरों में कमी करने और अन्य रियायतें दिए जाने के कारण पूरे वर्ष में 146 करोड़ रुपये की और 1981-82 में 115 करोड़ रुपये की हानि होगी। केन्द्र और राज्यों के बीच आयकर की राशि के विभाजन की जो पद्धति अपनाई गई है उसके अनुसार 1981-82 में केन्द्र को 29 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। निगम कर की दरों में कटौती किए जाने और कम्पनियों को अन्य रियायतें दिए जाने के कारण राजस्व की जो हानि होगी वह कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त की अग्रिम अदायगी कर देने से काफी हद तक संतुलित हो जाएगी। इसलिए 1981-82 में इस सम्बन्ध में, मैं राजस्व की किसी हानि की कल्पना नहीं कर रहा हूँ।

94. अब मैं अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी प्रस्तावों पर आता हूँ। मेरा बुनियादी दृष्टिकोण यही रहा है कि अतिरिक्त राजस्व अधिकतर बढ़े हुए उत्पादन से ही प्राप्त हो। किन्तु छठी आयोजना के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने की जरूरत है। तथापि, अतिरिक्त साधन जुटाने समय मैंने इस अनिवार्य आवश्यकता को भली भांति ध्यान में रखा है कि उपभोक्ताओं के माध्यम और गरीब वर्गों के लिए कोई कठिनाई पैदा न होने दी जाए और हमारे उद्योग के लघु क्षेत्र को पहले से अधिक मात्रा में राहत दी जाए।

95. सर्वप्रथम सीमा-शुल्कों के क्षेत्र पर विचार करते हुए, मेरा प्रमुख प्रस्ताव सहायक सीमा-शुल्कों के बारे में है। यह शुल्क 1973 के बजट में हर साल वार्षिक आधार पर लगाया जाता है। इस शुल्क को आगे भी लागू रखते हुए, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय के तौर पर सहायक शुल्कों की दरों को बढ़ा दिया जाए। हाल के वर्षों में हम एक काफी उदार आयात नीति का अनुसरण करते रहे हैं। भविष्य में भुगतान शेष की कठिन स्थिति को देखते हुए, विदेशी मुद्रा का सम्भाल कर रखने की जरूरत है। यदि शुल्क-दर व्यवस्था का सूक्ष्मज्ञ के साथ उपयोग किया गया तो हमने विदेशी मुद्रा को सम्भाल कर रखने और कुछ राजस्व जुटाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए मैं कुछ उचित अपवादों के साथ, सभी श्रेणियों के आयातों पर लगने वाले सहायक सीमा-शुल्क की दरों में मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे किसी वस्तु विप्रेष की अवतरित लागत (लैंडेड कॉस्ट) में तेजी से वृद्धि होने की बात पैदा नहीं होगी।

96. इस समय आयातित वस्तुओं पर सहायक सीमा-शुल्क मोटे तौर पर तीन खण्डों में लगता है। बुनियादी

कच्चे माल जैसी 60 प्रतिशत मूल्यानुसार तक आधारिक शुल्क लगने वाली मदों पर सहायक शुल्क 5 प्रतिशत मूल्यानुसार लगता है, अर्द्ध-संसाधित माल और मध्यवर्ती वस्तुओं जैसी मदों के मामले में, जिन पर आधारिक शुल्क 60 प्रतिशत मूल्यानुसार या ऊपर लेकिन 100 प्रतिशत से नीचे है सहायक शुल्क की दर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार है, और जहां आधारिक शुल्क की दर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार या उससे ऊपर है जैसे कि तैयार और उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में, वहां सहायक शुल्क की दर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार है। अन्य मामलों में सहायक शुल्क की दर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार है, सिवाय कच्चे पेट्रोलियम के, जिस पर 9.50 रुपए प्रति मेट्रिक टन की दर लागू होती है। कुछ ऐसी भी मदें हैं जिन पर सहायक शुल्क बिलकुल नहीं लगता। मेरा प्रस्ताव है कि जहां सहायक शुल्क की दर इस समय 5 प्रतिशत है, वहां इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार, जहां इस समय 15 प्रतिशत है वहां 20 प्रतिशत मूल्यानुसार और जहां इस समय 20 प्रतिशत है वहां इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। किन्तु मैं कच्चे पेट्रोलियम पर लगने वाले सहायक शुल्क में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं करूंगा।

97. जो दृष्टिकोण मैंने ऊपर स्पष्ट किया है उसी के अनुरूप मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि पूजी उपस्कर की कतिपय मदों के सम्बन्ध में जिन्हें इस समय सहायक सीमा-शुल्क से पूरी छूट मिली हुई है वह छूट वापस ले ली जाए और उन पर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सहायक सीमा-शुल्क लगा दिया जाए। यह वृद्धि अन्य चीजों के साथ-साथ 'परियोजना आयातों' के रूप में मशीनरी के आयात पर और मशीनरी की अन्य मदों के आयात पर भी लागू होगी, जिन पर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर लागू होती है। इस उपाय से अतिरिक्त राजस्व तो मिलेगा ही, साथ ही मशीन निर्माण के स्वदेशी उद्योग का भी अतिरिक्त संरक्षण मिलेगा जिसे पिछले दिनों में निवेश वस्तुओं की लागत में हुई अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड़ा है।

98. मैंने पहले कहा था कि मैं सहायक सीमा-शुल्कों की प्रस्तावित वृद्धि से कुछ मदों को अलग रखूंगा। खाद्य तेल जैसी आवश्यक मदों के आयात पर प्रस्तावित वृद्धि नहीं की जाएगी। किरोसीन और उच्च स्फुरित वाले जीजल तेल जैसे थोक पेट्रोलियम उत्पादों और संकट-निरोधक भंडार बनाने के प्रयोजन से आयात किए गए इस्पात पर भी सहायक सीमा शुल्क की बढ़ी हुई दर लागू नहीं होगी। जिन मदों पर पिछले दिनों स्वदेशी उत्पादों की कीमतों के साथ समानत रखने की दृष्टि से आयात-शुल्क की दरों में परिवर्तन किया गया है, उनको भी बढ़ी हुई दर की परिधि से बाहर रखा गया है। इसके अलावा शुल्क दर और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जी.ए.टी.टी.) के अन्तर्गत अपनी वचनबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि तीन मदों पर सहायक शुल्क छोड़ दिया जाए; इसमें कुछ राजस्व का

त्याग करना पड़ेगा। इन प्रस्तावों के और ब्यौरे वजट पत्रों में उपलब्ध हैं।

99. इन प्रस्तावों से लगभग 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

100. मेरा अगला प्रस्ताव अखबारी कागज पर आयात शुल्क लगाने के बारे में है। इस समय यह मद पूरी तरह शुल्क-मुक्त है। अखबारी कागज के आयात पर काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इस मद पर एक साधारण-सी दर से सीमा शुल्क क्यों न लगाया जाए। इसलिए मैं आयातित अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से प्रभावी सीमा-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस उपाय से लगभग 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

101. स्टेनलेस स्टील की छड़ों और तार-डंडों के आयात पर इस समय 75 प्रतिशत की दर से शुल्क लगता है, क्योंकि उनका उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह विश्वास करने का कारण मौजूद है कि इनमें से कुछ आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल बर्तन बनाने के काम आने वाली पट्टियां और चादरें बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैं स्टेनलेस स्टील की छड़ों, डंडों और तार-डंडों पर लगने वाले प्रभावी सीमा-शुल्क को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 175 प्रतिशत मूल्यानुसार करना चाहता हूं। किन्तु मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि इस वृद्धि से स्टेनलेस स्टील के तार-डंडों, जो कि तार खींचने के काम आते हैं, के आयात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस उपाय से 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

102. प्लेन गैपट बेयरिंग पर लगने वाले आधारिक सीमा-शुल्क को भी 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस वृद्धि से थिन-वाल्ड बेयरिंग जैसे बेयरिंगों का बड़े पैमाने पर किया जाने वाला आयात कम हो जाना चाहिए क्योंकि इनके आयात में स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इस प्रस्ताव से 2.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। इसी प्रकार के उद्देश्य से ही, कम्प्यूटर और कम्प्यूटर के कल-पुर्जों पर लगने वाले आधारिक सीमा-शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस वृद्धि से 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

103. अब मैं उत्पाद-शुल्कों पर आता हूं। सदन को याद होगा कि 1978 में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (वस्त्र और वस्त्र वस्तुएं) अधिनियम पारित किया गया था जिसके अनुसार कतिपय वस्त्रों और वस्त्रों से बनी वस्तुओं पर लगने वाले आधारिक उत्पाद-शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाया गया था। यह सोचा गया था कि इस उत्पाद-शुल्क से मिलने वाले राजस्व का उपयोग

कंट्रोल के कपड़े पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा। कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और उस में भी उन धोतियों और भाड़ियों के अधिक उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो कि खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के गरीब वर्गों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इसके परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की व्यवस्था आगामी वर्ष में बढ़कर लगभग 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से वर्तमान दरों पर लगभग 66 करोड़ रुपए का ही राजस्व प्राप्त होगा। इसलिए मैं इस समय इस शुल्क के अंतर्गत आने वाली सभी मदों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दर को आधारीक उत्पाद-शुल्क के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे लगभग 33 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी और कंट्रोल के कपड़े के बढ़े हुए परिव्यय को पूरा करने के लिए मदद मिलेगी।

104. जहां तक विशेष उत्पाद-शुल्कों का संबंध है मैं उन्हें मौजूदा दरों पर ही लागू रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय जो छूटें मिल रही हैं वे भी बराबर लागू रहेंगी।

105. संघ उत्पाद-शुल्कों से संबंधित मेरे बाकी प्रस्ताव मुख्य रूप से सरलीकरण और अधिक स्पष्टता की दृष्टि से तैयार किए गए हैं।

106. सम्मानित सदस्यों को मालूम होगा कि दियासलाई (माचिस) पर लगने वाले शुल्क का एक क्रमबद्ध ढांचा मौजूद है, जिसके अंतर्गत मशीनीकृत क्षेत्र को 7.20 रुपए प्रति गुर्स डिविया, मध्यवर्ती क्षेत्र को 4.50 रुपए और कुटीर क्षेत्र को 1.60 रुपए प्रति गुर्स उत्पाद-शुल्क देना पड़ता है। दांडेकर समिति की रिपोर्ट और सरकार द्वारा किए गए विशेष अध्ययन की दृष्टिगत रखते हुए यह जरूरी हो गया है कि कुछ श्रम-प्रधान प्रक्रियाओं के मशीनीकरण के प्रति मध्यवर्ती क्षेत्र के एककों की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शुल्क की रियायती दर यानी मध्यवर्ती क्षेत्र के एककों के लिए 4.50 रुपए और कुटीर एककों के लिए 1.60 रुपए की दर उस हालत में उपलब्ध नहीं होगी यदि फ्रेम-भराई करने, मसाले में तीलियों की हवाई करने, डिविया बनाने, डिविया भरने, लेबल चिपकाने और बैंड रोल लगाने और पैक करने की श्रम-प्रधान प्रक्रियाओं में बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि ये एकक उपर्युक्त में से किसी भी प्रक्रिया के लिए बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें 5.50 रुपए प्रति गुर्स डिविया की दर से शुल्क देना होगा जो कि पूर्णतः मशीनीकृत क्षेत्र पर लगने वाली 7.20 रुपए की दर और गैर-मशीनीकृत मध्यवर्ती क्षेत्र पर इस समय लगने वाली 4.50 रुपए की दर के बीच में होगी। मैं यह बतला देना चाहूंगा कि यह परिवर्तन राजस्व के प्रयोजन से नहीं किया गया है। इसमें आणख केवल यही है कि उत्पाद-शुल्क की व्यवस्था के जरिये गैर-मशीनीकृत क्षेत्र की रोजगार क्षमता को सुरक्षित रखा जाए।

107. मध्यवर्ती क्षेत्र को कुटीर क्षेत्र में समूचे करने से रोकने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुल्क की न्यूनतम दर का लाभ कुटीर क्षेत्र के असली एककों को ही मिले, यह प्रस्ताव किया जाता है कि रियायती दरों पर कुटीर क्षेत्र के एककों द्वारा दी जाने वाली निकासियों (क्लीयरेंस) पर फिर से अधिकतम सीमा (सीलिंग) लगा दी जाए। 1200 लाख माचिस प्रति एकक प्रति वर्ष की नई प्रस्तावित सीमा 1980 के बजट से पहले विद्यमान 750 लाख माचिस की सीमा से काफी ज्यादा उदार है। उत्पादन और निकासी की पद्धति पर निगरानी रखी जाएगी और यदि परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता हुई तो इस सीमा पर फिर से विचार किया जाएगा। मैंने जो परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है वे उद्योग के सभी अवयवों के लिए उचित हैं और उनका उद्देश्य सर्वोत्तम संभव तरीके से रोजगार और उत्पादन दोनों को बढ़ावा देना है।

108. युक्तिसंगत बनाने (रेशनलाइजेशन) का एक और उपाय उस रियायत के संबंध में है जो टेरिफ की मद 68 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के उन निर्माताओं को उपलब्ध है जो "जॉब" आधार पर काम करते हैं। वर्तमान योजना के अंतर्गत शुल्क, प्रधान निर्माता द्वारा 'जॉब' कामगार को दिए जाने वाले जॉब प्रभागों पर ही प्रभावी रूप से वसूल किया जाता है। किन्तु इन योजना के संचालन में कई कठिनाइयां महसूस की गई हैं, खास तौर से इन प्रश्न पर कि 'जॉब कार्य' क्या है। ऐसे मामले भी देखने में आए हैं जिनमें कुछ निर्माताओं ने इस रियायत का अनुचित लाभ उठाया है। इसलिए मैं इस योजना के स्थान पर एक दूसरी योजना चालू कर रहा हूँ जिसमें जॉब कामगार को छदा किए गए जॉब प्रभागों पर अलग से शुल्क लगाने की बजाय शुल्क, प्रधान निर्माता द्वारा, तैयार माल के मूल्य पर दिया जाएगा। इस कदम का आमनीर पर उन सहायक एककों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए जो जॉब के आधार पर काम करते हैं।

109. मैं टायरों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की प्रविष्टि और दर ढांचे को भी युक्तिसंगत बनाना चाहता हूँ जिसका उद्देश्य विधायी आशय को अधिक स्पष्ट करना और खास तौर से, बुलडोजरों, स्कैरों और मिट्टी हटाने के अन्य उपकरणों में काम आने वाले सड़क-भिन्न (आफ-द रोड) टायरों के बारे में वर्गीकरण और निर्धारण संबंधी विवादों के लिए कम से कम गुंजाइश छोड़ना है। आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करते समय मैंने कृषि के ट्रैक्टरों और उनके ट्रेलरों, दोनों के टायरों के संबंध में वर्तमान शुल्क की दरों और शुल्क की रियायतों को लागू रखने का ध्यान रखा है।

110. एक अन्य बड़ा क्षेत्र जहां टेरिफ की प्रविष्टियों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ में उत्संबंधी प्रविष्टियों के अंतर्गत अलौह धातुओं का है। इन धातुओं की रही और स्कैर के निर्धारण के प्रश्न पर काफी वाद-विवाद होता रहा है। इन वाद-विवादों को शान्त करने के लिए इन धातुओं की रही और

स्कैप को विनिर्दिष्ट रूप में तत्संबंधी टेरिफ प्रविष्टियों के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है।

111. उपर्युक्त के अलावा, कनिष्ठ टेरिफ प्रविष्टियों में कुछ अन्य संशोधन करने और पोलिएस्टर फिल्म के लिए एक अलग टेरिफ मद जोड़ने का भी प्रस्ताव किया जाता है। इन परिवर्तनों का ब्योरा बजट-पत्रों में देखा जा सकता है।

112. अब मैं उस प्रस्ताव की ओर आता हूँ। जो राज्य सरकारों की, काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बिस्की-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने की योजना इस समय चीनी, तंबाकू और कुछ वस्त्र मदों पर ही लागू होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व के बीच, जहाँ तक संभव हो, 2:1 का अनुपात रहना चाहिए। मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में मैंने यह आश्वासन दिया था कि कुल मिलाकर इन वस्तुओं के सम्बन्ध में यह अनुपात प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।

113. अब मैंने विचार किया है कि इस आश्वासन को अधिक से अधिक कैसे पूरा किया जा सकता है। इसका सबसे आसान उपाय यह होगा कि केन्द्र और राज्यों के बीच, सिगरेटों से प्राप्त होने वाले राजस्व के बंटवारे के लिए अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए। सिगरेटों पर लागू होने वाली सम्मिश्र दर में, आधारीक उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के बीच इस समय जो 76:24 का अनुपात मौजूद है, उसके मुकाबले, 72.5:27.5 का अनुपात रखने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके साथ ही सम्मिश्र दर में, मात्रानुसार शुल्क के तत्व में 21.00 रुपए से 21.25 रुपए प्रति हजार के हिसाब से एक समान वृद्धि कर दी जाएगी। सिगरेटों से कुल मिलाकर मिलने वाले राजस्व में कोई खास घट-बढ़ नहीं होगी। इसलिए निर्माताओं के पास सिगरेटों की कीमत बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होगा। इन सब परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप, एक और आधारीक और विशेष उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व और दूसरी ओर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के बीच, विद्यमान समग्र अनुपात चीनी, तंबाकू और वस्त्रों को एक साथ लेने पर, बढ़कर 2:1 हो जाने की आशा है। इसके फलस्वरूप लगभग 21.72 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अंतर्गत राजस्वों में निकल कर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के अंतर्गत राजस्वों में चली जाएगी।

114. मेरे पास एक छोटा प्रस्ताव और भी है जिसमें मूल रूप से राज्य सरकारों को दिलचस्पी हो सकती है। औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम, 1959 के अंतर्गत उन औषधियों और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद-शुल्क लगता है जिनमें ऐल्कोहॉल, स्वापक पदार्थ और स्वापक दवाएं होती हैं। मेडिक प्रणाली को अपनाने के लिए और कतिपय मामलों में शुल्क के परिवर्तन को रोकने के लिए उक्त अधिनियम में कतिपय परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। किन्तु

राजस्व की दृष्टि से इन प्रस्तावित परिवर्तनों का बहुत कम महत्व है।

115. अब मैं अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में दी जाने वाली रियायतों पर आता हूँ। यह सरकार इस बात के लिए बचन-बद्ध है कि वह रोजगार और उद्यमधर्मता के व्यापक विकास के हित में, लघु उद्योग के संवर्धन के लिए सशक्त नीति अपनाएगी। तदनुसार, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्पाद-शुल्क योग्य 72 वस्तुओं पर लागू होने वाली उत्पाद-शुल्क संबंधी रियायतों की सामान्य योजना के अंतर्गत शुल्क की छूट की सीमा को, निकासियों के मूल्य के रूप में, 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया जाए। 7.5 लाख रुपए से अधिक मूल्य की निकासियों पर मौजूदा रियायती शुल्क का लाभ मिलता रहेगा जो हम समय, एक वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपए की निकासी तक लागू होने वाली उत्पाद-शुल्क की धरों के तीन-चौथाई तक सीमित है। इस उपाय से काफी बड़ी संख्या में लघु निर्माताओं को लाभ मिलना चाहिए और उनमें बड़े एककों के साथ अधिक सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने की क्षमता आ जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्ग लघु उद्योग को उपलब्ध रियायतों की योजना के इस विस्तार का स्वागत करेंगे।

116. कुछ उत्पादों, खास तौर से, मद 68 की वस्तुओं और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लघु निर्माताओं को इस समय उपलब्ध उत्पाद-शुल्क संबंधी रियायतों के अंतर्गत, पात्रता की एक कसीटी संयंत्र और मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश का मूल्य है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे पूंजी निवेश की पात्रता की सीमा को, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत लघु एककों की संशोधित परिभाषा के अनुरूप, 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए कर दिया जाए। यहां भी मुझे विश्वास है कि सभी सम्मानित सदस्य मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे।

117. पिछले बजट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क संबंधी बहुत-सी रियायतों की घोषणा की थी। इसी दिशा में एक और कदम के रूप में, मैं आयात-शुल्क संबंधी रियायतों के व्यापक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। ताकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पूंजी उपस्कर की 59 नई मदें और कच्चे माल और संघटकों की 23 नई मदें इसके अंतर्गत आ जाएं।

118. इस समय, ऊनी उद्योग के हाथकरघा क्षेत्र को शुल्क संबंधी कोई विशेष रियायतें उपलब्ध नहीं हैं। इस क्षेत्र में वृद्धि की अच्छी संभावना है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिस प्रकार हाथकरघों पर बने सूती कपड़ों पर रियायतें उपलब्ध हैं उसी प्रकार हाथकरघों पर बने ऊनी कपड़ों पर प्रमत्स्करण (प्रोसेसिंग) अवस्था में लगने वाले शुल्क को काफी कम कर दिया जाए।

119. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि आयात-शुल्क की 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर कुछ और महत्वपूर्ण मध्यवर्ती शीपधियों पर भी लागू हो। ऐसा करने से स्वदेशी निर्माताओं को अधिक बुनियादी शीपधियों का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रलोभन मिलना चाहिए।

120. पिछले साल मैंने सूती और सूत-विस्कस मिश्रित होजियरी को पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया था। अब मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की मद 68 के अंतर्गत आने वाली सभी होजियरी वस्तुओं को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

121. एक दूसरी शुल्क संबंधी रियायत 'फ्लॉयड' कपड़े के बारे में है जहाँ उत्पाद-शुल्क को आधार कपड़े के शुल्क और 30 प्रतिशत मूल्यानुसार के वर्तमान स्तर से कम करके आधार कपड़े के शुल्क और 15 प्रतिशत मूल्यानुसार, इस विचार से किया जा रहा है कि वर्तमान शुल्क का बोझ खास तौर से फ्लॉयड कपड़े पर, आवश्यकता से अधिक है। इसके अलावा, छपाई उद्योग में काम आने वाले कलर स्कैनरों पर लगने वाले आधारीक सीमा शुल्क को 100 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है।

122. इस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में, यह समीचीन होगा कि हमारे अपंग भाईयों को कर संबंधी राहत पहुंचाने के लिए समुचित उपाय किए जाएं। अपंगों के लिए कृत्रिम अंग और पुनर्वास सहायक उपकरणों पर तो पहले से ही मद 68 के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट मिली हुई है। अब मैं नेत्रहीनों के काम आने वाली ब्रेल घड़ियों को भी उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

123. मैं ब्रेल कागज को भी उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जो नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें छापने के काम आता है।

124. इसके अलावा, मैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाक या हवाई जहाज से आयात की गई ब्रेल घड़ियों और श्रवण उपकरणों पर लगने वाले सीमा-शुल्क को भी काफी ज्यादा घटा देने का प्रस्ताव करता हूँ।

125. मैंने पहले जो सहायक सीमा-शुल्कों में वृद्धि करने की बात कही है, वह विकलांगों के साधनों, ब्रेल घड़ियों तथा पुर्जों, पंगुओं के लिए तिपहिया साइकिलों, श्रवण उपकरणों तथा पुर्जों जैसे सामान पर लागू नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि यह सदन खुले दिल से मेरे इन प्रस्तावों का समर्थन करेगा।

126. मैंने उत्पाद-शुल्कों और सीमा-शुल्कों में जिन विभिन्न प्रकार की रियायतों और राहतों की घोषणा की है उनके कारण पूरे वर्ष में 9.35 करोड़ रुपये के राजस्व का त्याग करना होगा।

127. मेरे कराधान प्रस्तावों से पूरे वर्ष में उत्पाद-शुल्क के रूप में लगभग 35.57 करोड़ रुपये की और सीमा-शुल्क के रूप में 285.00 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। मैंने जिन रियायतों की घोषणा की है वे उत्पाद-शुल्क के मामले में कुल मिलाकर 7.05 करोड़ रुपये और सीमा-शुल्क के मामलों में 2.30 करोड़ रुपये की बैठती है। इस प्रकार उत्पाद शुल्कों से 28.52 करोड़ रुपये और सीमा शुल्कों से 282.70 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति होगी। पूरे वर्ष इनसे केन्द्रीय राजकोष में 300.50 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

128. मुझे आशा है कि सम्मानित सदस्यों के ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी कि पिछले कुछ वर्षों में यह पहला बजट है जिसमें कि सामान्य राजस्वों को जुटाने के लिए उत्पाद-शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

129. अब मैं कुछ शब्द अपने सम्मानित साथी संचार मंत्री की ओर से भी कहना चाहूंगा। छठी पंचवर्षीय आयोजना में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के एक काफी बड़े कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसलिए यह समुचित होगा कि विभाग अपनी आयोजना का विस्तार करने के लिए युक्ति युक्त सीमा तक आन्तरिक साधन पैदा करे। कर्मचारियों को मंजूर किए गए अतिरिक्त महंगाई भत्ते और संचालन की लागत में हुई अन्य वृद्धियों के कारण विभाग की मौजूदा अधिशेष राशि पहले ही काफी कम हो चुकी है। इसलिए दूरसंचार की कुछ शुल्कदरों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। मापित दर टेलीफोन प्रणाली में टेलीफोन प्रभार की दर इस समय एक तिमाही में 250 कालों से ऊपर लेकिन 1750 कालों तक के लिए प्रति काल यूनिट 30 पैसे है। अब इस दर को बढ़ाकर 40 पैसे प्रति काल यूनिट करने का प्रस्ताव है। 3 मिनट की यूनिट अवधि वाली साधारण कालों के लिए मेनुअल ट्रंककाल प्रभारों को 100 किलोमीटर से अधिक किन्तु 200 किलोमीटर तक के दूरी-खंड के लिए 6 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये और 200 किलोमीटर से अधिक किन्तु 500 किलोमीटर तक के दूरी-खंड के लिए 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये किया जा रहा है। इन उपायों से पूरे वर्ष में 35.78 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। 1981-82 में अतिरिक्त राजस्व कोई 20 करोड़ रुपये होगा और डाक-तार विभाग की प्राप्तियों का अनुमान लगाते समय उसे हिसाब में ले लिया गया है। 'अवने-टेलीफोन-के-मालिक-बनिए' (ओ० वाई० टी०) प्रणाली के अंतर्गत टेलीफोन के कनेक्शनों के लिए जमा राशि की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस संशोधन से 1981-82 में अतिरिक्त जमा राशियों के रूप में सरकार को लगभग 5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इन संशोधनों का धीरा एक ज्ञापन में दिया गया है जो बजट पत्रों के साथ परिचालित किया जा रहा है। ये परिवर्तन संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू किए जाएंगे। डाक या तार की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

130. मैंने पहले बताया है कि कराधान की मीजदा दरों के अनुसार साधनों में 1810 करोड़ रुपए का अंतर रहने का अनुमान है। मैंने कर-संबंधी जो विभिन्न उपाय प्रस्तुत किए हैं और जो राहने देने का प्रस्ताव किया है, उनमें कुल मिलाकर केन्द्र को 271 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस प्रकार 1539 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह घाटा काफी बड़ा प्रतीत हो सकता है। लेकिन आर्थिक स्थिति को समग्र रूप से देखने पर मेरा यह विश्वास है कि यह घाटा राजकोषीय सूझबूझ की सीमाओं के भीतर ही है। बजट की मुद्रास्फीतिकारी संभावना को नीति विषयक उन सम्पूर्ण उपायों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए जिनकी रूपरेखा मैंने पहले बताई है। इन उपायों में उच्च उत्पादन और क्षमता के अधिक उपयोग के लिए बड़े प्रोत्साहन दिए गए हैं। इनके परिणाम-स्वरूप आने वाले वर्ष में पूर्ति में काफी वृद्धि होगी और जैसा कि मैंने बताया है, स्थिति में सुधार के लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। मैं पूर्ति की वृद्धि को बहुत अधिक महत्व देता हूँ क्योंकि मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रण में रखने के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। इन नीतियों में बचतों के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिए गए हैं जिनसे इस सम्बन्ध में अवश्य ही सहायता मिलेगी। इसके अलावा, मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीतियाँ इस प्रकार तैयार की जाएंगी, जिनसे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सरकार द्वारा की जाने वाली घाटे की वित्त-व्यवस्था ऋण के कुल मिलाकर संतुलित और नये-नये विस्तार की सीमाओं के अन्दर ही रहे।

131. माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक स्थिति बराबर कठिन बनी हुई है, लेकिन इसमें विकास और वृद्धि के भरपूर अवसर विद्यमान हैं। मैंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो ऐसी शक्तियों को अधिकतम समर्थन देता है जो स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ हमें वृद्धि के पथ पर अग्रसर कर सकती है। यह बजट छठी आयोजना में स्पष्ट रूप से निर्धारित हमारे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में हम सब के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है। आर्थिक नीति तो बस इतना ही कर सकती है और बाकी का काम तो इस पुरातन देश की जनता के परिश्रम, अनुशासन और सहज सद्भाव से ही पूरा होगा।

132. महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

ए० सी० तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(Budget Division)

BUDGET 1981-82

SPEECH OF

MINISTER OF FINANCE

New Delhi, 28th February, 1981

PART A

M/Finance (EAD) u.o. No. F. 15(3)-B(D)81

Sir,

It is my privilege, once again, to present the Budget to this august House.

1399 GI/80-3

2. The Budget for 1981-82 has been formulated in an economic situation which continues to be difficult, but also shows great improvement over the desperate conditions prevailing a year ago. The "Economic Survey" presented to the House this week contains a detailed review of developments in the past year. I shall, therefore, only review the highlights of the economic situation as a background to presenting the strategy of next year's budget.

3. Hon'ble Members will recall that when our Government took office in January 1980, we inherited an economy in extremely poor shape. It was reeling from a disastrous economic performance in 1979-80, when the Gross National Product declined by 4.5 per cent, and prices increased by over 21 per cent. Neglect and mismanagement of the infrastructure had produced a crisis situation in key sectors such as coal, power and railways.

4. Faced with this grim situation, our overriding objective was to arrest the deterioration and set the economy once again on the path of stability and growth. This was no easy task. The severe drought of 1979-80, and the accumulated problems in management of the infrastructure, cast a long shadow over 1980-81.

5. Efforts to improve infrastructure performance deserved and received the highest priority in 1980-81. A mechanism for crisis management was established, with special administrative arrangements to monitor and co-ordinate Government action in this area, and to set clear priorities. It took time for these efforts to bear fruit, but by the middle of the fiscal year, all the three sectors, power, coal and railways showed distinct improvement.

6. Power generation suffered in the early months of 1980-81 because of very low hydro-electric generation. This was a direct consequence of the acute drought of 1979, which left the reservoirs severely depleted through the lean summer months of 1980. Hydro-electric generation picked up after July when most of the reservoirs were replenished by the monsoon. There was also a very substantial improvement in thermal generation. The problems of coal availability which had plagued thermal power plants during 1979 were substantially overcome and rail movement of coal to thermal plants was organised on a priority basis. Strenuous efforts were also made to improve operational efficiency by initiating betterment and renovation programmes in the States with technical advice from Central Agencies. As a result, thermal electricity generation in November and December 1980 was 21 per cent higher than in the same months in 1979. For the year as a whole, electricity generation is likely to show an increase of about 6 per cent over 1979-80. However, in the second half of 1980-81 generation would be about 13 per cent higher than the second half of the previous year.

7. Coal production in 1980-81 also shows a marked improvement. The production of coal and lignite had remained more or less stagnant at about 106 million tonnes since 1976-77. This frustrating spell of stagnation has been broken and production is expected to exceed 115 million tonnes in 1980-81. Better availability of power was one of the important factors behind this improved performance.

8. The railways have shown improvement in the movement of freight in recent months, breaking a pattern of deterioration witnessed over the past three years.

9. Industrial production in 1980-81 reflected the progress made in removing infrastructure constraints. I have already mentioned that hydro-electric generation was very low in the first three months of 1980-81 because of the depletion of reservoirs. The resulting shortage of power depressed industrial production through much of the first half of 1980-81. However, with the easing of infrastructure constraints in the second half of the year, industrial production has picked up. For the year as a whole, it is likely to show a growth of about 4 per cent. This compares with a decline of 1.4 per cent in 1979-80.

10. In addition to efforts at improving infrastructure performance, the Government also took wide ranging measures

designed to create conditions conducive to rapid industrial expansion. Hon'ble Members will recall that the Budget for 1980-81 contained specific fiscal incentives designed to encourage investment activity. This was followed by the Industrial Policy Statement of July 1980 in which several promotional measures were announced. Steps were also taken in the course of the year to increase the flow of investment finance to industry. A new policy has been enunciated to permit investment funds from oil exporting developing countries to flow into new units in selected industries in the form of portfolio investment. The guidelines for issue of debenture were revised to permit more effective use of this instrument for mobilisation of funds.

11. Although the promotional impact of these measures could not manifest itself fully in 1980-81 because of infrastructure bottlenecks, they have undoubtedly set the stage for longer term industrial expansion in the coming years.

12. The performance of agriculture in 1980-81 gives every ground for satisfaction and provides great reassurance about the basic health of this vital sector of our economy. The weather in 1980-81 was favourable in most, but by no means all, parts of the country, and this created conditions conducive to an agricultural recovery. The total production of foodgrains in 1980-81 is likely to exceed 132 million tonnes, which is more than 23 million tonnes higher than in 1979-80. It will surpass the previous peak level achieved in 1978-79, and yet weather conditions were less favourable than in that year. The gains in foodgrains production in 1980-81 have been accompanied by a very substantial recovery in sugarcane production. Production of fibre crops was also good.

13. This excellent performance testifies to the soundness of the agricultural strategy we introduced in the late sixties. This strategy was vigorously pursued in 1980-81. A concerted effort was made to ensure adequate production of quality seeds. The area under high yielding varieties was expanded to 48 million hectares compared with only 35.2 million hectares in 1979-80. Large imports of fertilisers were undertaken to supplement domestic production. Fertiliser consumption in terms of nutrients is estimated to have increased from 5.26 million tonnes to 5.6 million tonnes. Expansion of irrigation received special attention and the agricultural extension machinery was strengthened to ensure a more effective transfer of technology.

14. The excellent performance of agriculture, combined with the beginning of a recovery in industry, is likely to produce an overall growth of 6.5 per cent in the Gross National Product. This is an important achievement, but I must caution against complacency. The progress made needs to be consolidated, and further momentum must be built up if the recovery of 1980-81 is to mature into full-fledged growth next year. This calls for a realistic assessment of the strengths, as well as the weaknesses, of the economy.

15. The economy continued to be subject to inflationary pressure during 1980-81 although there can be no doubt that there was a marked improvement over 1979-80. The increase in prices during 1980-81 upto the end of January 1981 has been 13.5 per cent. It was nearly 20 per cent in the same period of the previous year. Inflationary pressures were particularly severe in the first half of the year because of the after effects of the drought of 1979 and this was especially evident in the behaviour of sugar, gur and khandasari prices. With the improvement in the supply situation in the second half of the year, there was a definite improvement. Prices declined from the middle of October to the end of December. They have risen since then, partly because of the unavoidable increase in petroleum prices effected in January. However in recent weeks, the increase in prices has moderated.

16. I must caution however that although inflation has abated, it has not been overcome. The economy remains subject to continuing cost push pressures, including especially the transmission of international inflation through rising prices of oil and other essential imports. Since these cost push pressures are likely to persist, continued vigilance is

required in the coming year. It is essential to evolve a strategy for coping with cost push inflation effectively by tackling the problem at its roots. This is not only a matter of demand management. It also requires an all out effort to increase efficiency and achieve higher productivity.

17. Monetary and credit policies in 1980-81 were tailored to the requirements of the inflationary situation and commercial credit was strictly regulated. In addition, steps were taken to ensure that the distribution of bank credit conforms to our economic and social priorities. The Reserve Bank has evolved guidelines to ensure that an increasing share of priority sector credit is directed to weaker sections, especially those identified in the 20 point programme. According to these guidelines, 40 per cent of priority sector lending is to be earmarked for the agricultural sector. Half of the direct lending by commercial banks to agriculture and allied activities will be directed to small and marginal farmers and agricultural labourers. Furthermore, 12.5 per cent of total credit advanced to small scale industries will be reserved for rural artisans, village craftsmen and cottage industries.

18. The expansion of banking in the rural areas is continuing and the programme of establishing Regional Rural Banks has been accelerated. There were only 60 such banks at the end of December 1979. There will be one hundred by the end of March 1981. Another 25 Regional Rural Banks will be established in the year 1981-82. It is proposed to increase their number to 170, covering 270 districts, by the end of the Sixth Plan. A National Bank for Agricultural and Rural Development will be established as an apex institution to meet the credit needs of the rural community and a bill to this effect will be introduced shortly.

19. This is an appropriate occasion to inform the House that we have decided to undertake a major re-organisation of the Life Insurance Corporation in order to strengthen its ability to meet the challenges of the future. The Corporation has an impressive record of extending insurance services to the community. In the process it has grown very considerably in size. It has, therefore, become desirable to restructure the Corporation into more manageable units in the interest of operational efficiency, and also to allow an element of healthy competition. Accordingly, we have decided to re-organise the Corporation into five independent units with a co-ordinating body to provide supervision and guidance on matters of common interest. I have no doubt that these changes will improve the quality of service rendered to policy holders. This re-organisation will impart a greater degree of dynamism into the working of these institutions, and this will help to extend life insurance into the rural areas, where only limited headway has been made so far.

20. The balance of payments situation facing the country gives cause for concern. Rising prices of imported oil have added enormously to the external payments burden on the economy. The import bill for crude oil and petroleum products is likely to reach Rs. 5,600 crores in 1980-81, compared with only Rs. 1,677 crores two years ago. Most of the increase is due to the increase in oil prices. The total import bill in 1980-81 is likely to be around Rs. 11,300 crores whereas exports are projected to be only Rs. 7,100 crores. Even after allowing for the surplus on net invisibles, the country has to finance a balance of payments deficit of about Rs. 2,000 crores in 1980-81. This is much larger than the amount of external assistance available, and it has led to a significant drawdown of foreign exchange reserves. It is, therefore, essential to evolve a strategy for bringing the balance of payments under control. The Government has already taken a number of steps in this direction.

21. High priority has been accorded to oil and natural gas exploration in order to reduce our dependence on imported supplies as much as possible. The Oil and Natural Gas Commission has found evidence of hydrocarbons in several structures both offshore and onshore and it is essential to pursue the exploration and development efforts with all the resources at our command. To this end, an ambitious programme is envisaged for the Oil and Natural Gas Commission and Oil India Ltd. The urgency of the situation is also such that the Government has decided to supplement our domestic capability by engaging foreign parties on con-

tract, on a production sharing basis, to hasten the pace of exploration and development of potential oil fields. It is expected that the foreign companies selected under this scheme will commence work in the second half of 1981-82.

22. The balance of payments situation also calls for strong support to exports and the Government has taken several important initiatives in this regard recently. Hon'ble Members will recall that in my Budget Speech last year I stated that the Government had taken a decision to establish an Export-Import Bank to assist in the financing of international trade. The details of this proposal have now been worked out, and it is proposed to introduce a Bill in the current session for setting up the Export-Import Bank as a Statutory Corporation. I am providing Rs. 70 crores in the Budget for this purpose.

23. There is also considerable scope for import substitution by increasing domestic production and expanding capacity in sectors such as steel, cement, fertiliser, non-ferrous metals and oilseeds. This is being vigorously pursued.

24. The strategy of the Budget I am about to present flows from my assessment of the state of the economy. We have come out of the crisis situation which prevailed a year ago. The agricultural sector has recovered and is well poised for continued growth. The industrial recovery is as yet partial, but the various policy initiatives already taken have created conditions favourable for an industrial revival. With further improvement in infrastructure performance, the constraints on industry in the coming year should be substantially eased. The emphasis in 1981-82 must therefore shift from crisis management to growth.

25. The tasks ahead of us have been clearly indicated in the Sixth Plan, which has now been approved by the National Development Council. The Plan establishes a target of 5.2 per cent growth per annum and calls for an ambitious public sector investment programme of Rs. 97,500 crores. As in the past agricultural development, with special emphasis on the weaker sections, is the centrepiece of our development strategy. But the Sixth Plan also identifies some other areas which have become especially critical. The energy-transport system comprising such critical sectors as power, coal, oil, ports and railways, requires massive investments if these sectors are not to become a constraint upon economic growth.

26. The Budget must make a beginning in undertaking these large and urgent tasks. But it must do so in the full knowledge that the threat of inflation has not been fully overcome. The fiscal deficit should therefore be kept within tolerable limits. At the same time, taxation must be used judiciously so that it does not fan the flames of inflation as happened in 1979-80.

27. Along with fiscal discipline we must also take steps to encourage the flow of private savings into the financial system. Only thus can we ensure adequate availability of non-inflationary financing to meet the rapidly expanding needs of the economy. This flow of resources into the financial system is threatened in two ways and we must tackle both.

28. First of all, it is threatened by the pernicious growth of the black economy. This generates income flows which cannot easily surface in the financial system, and are therefore directed into socially harmful activity such as hoarding, profiteering, speculation and wasteful consumption. This only stokes the fires of inflation. The Government has recently taken a major initiative to direct some of the resources circulating in the black economy into the public exchequer through the sale of Special Bearer Bonds. Further action on a wide front is necessary to check the generation of black money so that this social evil is progressively eliminated from our society.

29. A second impediment to financial savings is the existence of high rates of inflation. In an inflationary situation it becomes essential to provide adequate incentives to financial savings. Since bank deposits are the most important single mechanism for financial savings, it has been decided

to raise the interest rate on maturities from one and upto five years. An announcement to this effect is being made by the Reserve Bank. The interest rate paid on deposits above 1 year maturity and upto 2 years will be raised from 7 per cent at present to 7.5 per cent. The rate paid on deposits above two years and upto three years will be raised from 7 per cent at present to 8.5 per cent. The rate paid on deposits above three years maturity will be raised from 8.5 per cent at present to 10 per cent.

30. The interest rate paid by banks on deposits above 5 years is unchanged, but a new National Savings Certificate will be issued with a maturity of 6 years which will carry an interest rate of 12 per cent. This will provide the necessary incentive for encouraging longer term savings.

31. In addition to these measures, I propose to raise the interest rate ceiling on debentures from 12 per cent at present to 13.5 per cent. This is in line with the other interest rate changes proposed, and it will encourage large industrial units to raise their requirements of investment finance through their own efforts. It is essential that these units, which have the capacity to mobilise resources through the financial markets, should make greater efforts in this direction and thus reduce the burden on the term lending institutions.

32. At present, public companies are permitted to accept deposits from the public upto 25 per cent of the aggregate of their paid up share capital and free reserves. They are also allowed to accept deposits upto 10 per cent of paid up capital and free reserves either from their shareholders or from others when guaranteed by a Director of the company. These limits do not apply to inter-company deposits. These provisions governing company deposits will be continued. However, it is proposed to impose a ceiling of 15 per cent on the interest rate which can be paid on these deposits. The requisite orders giving effect to these decisions are being issued.

33. As a further step in facilitating investment in industry we have decided to relax the requirement under the Stock Exchange guidelines that promoters can only hold a maximum of 40 per cent of the equity of a new company. This provision conflicted in some cases with the requirement of the financial institutions that promoters put up a minimum percentage of the total cost of the project. This potential contradiction between two different requirements had given rise to considerable difficulties in the implementation of new projects. In order to overcome these problems, promoters will be allowed to hold higher equity than the 40 per cent limit during the initial stages of a project. However, equity holdings above 40 per cent will have to be divested within three years from the date of commercial production by an offer of sale to the general public. This rationalisation should speed up the implementation of new projects in industry.

34. I am confident that these wide-ranging measures will help to encourage the flow of savings into the financial system and increase the availability of funds for industrial investment. They create highly favourable conditions for growth in the coming year.

35. Having outlined the broad approach I have adopted in formulating the Budget and some associated policy initiatives, I will now turn to the Revised estimates for 1980-81 and the Budget estimates for 1981-82.

Revised Estimates for 1980-81

36. The Budget estimates for 1980-81 had envisaged a deficit of Rs. 1,445 crores. However, as a result of discussions between the States and the Planning Commission the State Plan outlays were increased in a number of cases. Central assistance for State Plans was increased by Rs. 310 crores. We have also to provide additional assistance of Rs. 58 crores to the Rural Electrification Corporation. The provision of short term loans to the States for supply of agricultural inputs also had to be increased by Rs. 25 crores.

37. In addition, the Central Government has to provide assistance of Rs. 90 crores to the States to help in flood relief work. Special loan assistance of Rs. 76 crores is being provided to certain North Eastern States including Assam to meet the gap in their resources caused by their exceptional difficulties.

38. A larger provision for subsidies is being made than originally envisaged. The provision for net outgo on imported fertilisers is being increased by Rs. 104 crores. The provision for food subsidy, subsidy on controlled cloth and provision for cash compensatory support and market development for exports are also being increased by Rs. 110 crores.

39. The provision for Defence expenditure has to be increased by Rs. 200 crores.

40. The financial position of certain public sector undertakings did not show the recovery anticipated at the Budget stage. Additional non-Plan assistance of Rs. 104 crores to these undertakings has therefore become necessary.

41. Turning to the Central Plan expenditure, I am happy to inform the House that expenditure in crucial sectors like power, coal and petroleum has been satisfactory. The House will also be happy to note that the level of disbursements of the Agricultural Refinance and Development Corporation has far exceeded the initial Budget estimates, and I am, therefore, providing an additional sum of Rs. 126 crores to the Corporation. An additional provision of Rs. 50 crores is being made for Industrial Development Bank of India to enable it to meet its rising commitments. In certain sectors like steel and civil aviation, there has been a shortfall in internal resources generation and budgetary support for their Plans has to be significantly stepped up. There may be some shortfalls in the Plan expenditure in some sectors. However, even after taking these into account, the budgetary support for the Central Plan in 1980-81 will be Rs. 297 crores higher in the Revised estimates.

42. The total expenditure of the Central Government is now estimated at Rs. 22,808 crores compared with Rs. 21,467 crores in the Budget.

43. Turning to receipts, I am happy to inform the House that despite the concessions in income-tax allowed in the Budget for 1980-81, tax revenues have not suffered. My judgement that lower rate of taxation will promote better voluntary compliance seems to have been vindicated. The receipts from Corporation tax would be higher by Rs. 35 crores compared with the Budget estimate of Rs. 1515 crores. Receipts from Union Excise duties are also estimated to be higher by Rs. 99 crore, compared with the Budget estimate of Rs. 6265 crores. The receipts from Customs duties are likely to exceed the Budget estimate of Rs. 2989 crores by as much as Rs. 361 crores in the current year due to larger imports, and higher international prices. After deducting the States' share of various taxes, the net tax revenue of the Centre is now estimated to be Rs. 419 crores more than the Budget estimate of Rs. 8922 crores.

44. Capital receipts too, show an improvement of Rs. 245 crores over the Budget estimate of Rs. 7,694 crores. This is because of higher market borrowing of Rs. 104 crores and estimated receipts of Rs. 200 crores from the sale of Special Bearer Bonds, offset by some shortfalls elsewhere.

45. Total receipts are now estimated at Rs. 20,833 crores compared with the Budget estimates of Rs. 20,022 crores. The current year is now expected to close with a deficit of about Rs. 1,975 crores. The House will appreciate that almost the entire increase in the budgetary deficit is accounted for by larger budgetary support for State and Central Plans.

Budget Estimates for 1981-82

46. The Budget for 1981-82 reflects the objectives, priorities and programmes of the Sixth Plan. Plan outlays of the Centre, States and Union Territories in 1981-82 are estimated at Rs. 17,479 crores, compared with Rs. 14,593 crores in Budget estimates 1980-81. This represents an increase of nearly 20 per cent. The Plan outlay of the Centre

for 1981-82 is being stepped up very considerably to Rs. 8,619 crores from Rs. 7,340 crores in Budget estimates 1980-81, an increase of 17.4 per cent. This will be financed by budgetary support of Rs. 6,309 crores, and internal and extra budgetary resources of Public Sector Undertakings of Rs. 23,10 crores. The total of the approved Plan outlays of States and Union Territories will be Rs. 8,860 crores as against Rs. 7,253 crores in Budget estimates 1980-81, that is, an increase of 22 per cent. A provision of Rs. 3,462 crores has been made for Central assistance for the Plans of the States and Union Territories.

47. Agriculture has a preponderant role in our economy and its development sets the pace for the economy as a whole. The Annual Plan outlay for agriculture in the Central and State Plans has been stepped up to Rs. 1,047 crores from Rs. 925 crores in Budget estimates 1980-81. Expansion of the area under irrigation is the most important single factor enabling a shift to high productivity scientific farming. Accordingly it is proposed to add 2.5 million hectares under irrigation in 1981-82. The outlay for major and medium irrigation in the Annual Plan of the Centre and States for 1981-82 is being raised substantially to Rs. 1,408 crores from Rs. 1,213 crores in Budget 1980-81. The outlay on minor irrigation will be Rs. 301 crores compared with Rs. 266 crores in 1980-81.

48. Parallel with the effort at boosting total agricultural production, the Annual Plan lays great stress on special programmes to benefit the weaker sections of rural society such as landless labour, small and marginal farmers, rural artisans and scheduled castes and scheduled tribes. One of the important programmes which this Government has launched for this purpose is the National Rural Employment Programme. We are providing Rs. 180 crores in the Central Plan for this programme and this will be matched by an equal amount from the States.

49. Another important initiative aimed at helping the weaker sections is the Integrated Rural Development Programme. This programme absorbs the earlier complementary, and sometimes overlapping, programmes aimed at particular sections of the population. We have provided Rs. 198 crores for this programme as well as for special programmes such as Desert Development and Drought Prone Area Programmes. With an equivalent contribution from the States, it is expected that the Integrated Rural Development Programme will help 3 million families to go above the poverty line in 1981-82.

50. Central assistance for the Special Component Plans for Scheduled Castes was introduced in the very first Budget of the present Government. We have provided Rs. 110 crores for the next year. In addition, Rs. 13 crores will be invested in the Scheduled Castes Development Corporations of States. Along with an equal contribution from the States, this will enable these Corporations to raise substantial funds from the financing institutions. The tribal sub-plan, which is the vehicle for the development of tribal areas will receive an augmented provision of Rs. 85 crores during 1981-82, compared with Rs. 70 crores in 1980-81. A provision of Rs. 92 crores has been made for the Special Hill Development Programme compared with Rs. 61 crores in 1980-81.

51. In pursuance of the Government's policy to accelerate the provision of safe drinking water in problem villages, an amount of Rs. 110 crores has been allocated in 1981-82. Together with the provisions made in the State Plans, this would enable about 36,000 additional villages to be covered during the next year.

52. The Annual Plan accords high priority to the all important task of expanding capacities in sectors such as oil, coal and power. It is proposed to provide Rs. 580 crores for coal and lignite projects in 1981-82. This represents an increase of 31 per cent over the provision of Rs. 443 crores in 1980-81.

53. Large increases have also been made in the outlay for power in the Central Plan. We have provided Rs. 721 crores in 1981-82 compared to Rs. 520 crores in the last Budget. This reflects the expanding role of the Centre in the power sector. We propose to take up the Dulhasti Project in Jammu and Kashmir and the Koel Karo project in Bihar in the Central sector in the coming year. The total outlay for the power sector in the State and Central Plans taken together is Rs. 3326 crores compared to Rs. 2745 crores pro-

vided in the Plan for 1980-81. Additional generating capacity of 3000 MW is expected to be commissioned during 1981-82. The Rural electrification programme provides for electrification of 22000 villages and energisation of 4.25 lakh pump-sets in the coming year.

54. In keeping with the high priority accorded to exploration and development of oil and natural gas resources, the Plan outlay for the petroleum sector has been increased to Rs. 1011 crores in 1981-82 compared with Rs. 780 crores in the current year. An outlay of Rs. 67 crores is proposed in the petro-chemical sector.

55. An outlay of Rs. 796 crores is being provided for steel in 1981-82. A significant development in this area is the recent commissioning of the Demonstration Plant for Sponge Iron Production at Kothagudem. This project is of special significance to India since the technology for production of sponge iron by using non-coking coal will enable us to overcome the constraints imposed by the limited reserves of coking coal in our country.

56. The Annual Plan for 1981-82 envisages a significantly higher outlay of Rs. 223 crores for minerals development against Rs. 130 crores in 1980-81. This includes a provision of Rs. 90 crores for the Orissa Aluminium Project which will be implemented by the new National Aluminium Company registered with headquarters at Bhubaneswar in Orissa. The bulk of the project cost is expected to be financed by external credit and commercial borrowings.

57. In tune with our concern for improving transport facilities, we have enhanced the outlay in the Central Plan for the transport sector to Rs. 1535 crores from Rs. 1351 crores in 1980-81. Hon'ble Members are already aware that a substantial increase has been made in the Plan outlay of the Railways from Rs. 760 crores in 1980-81 to Rs. 980 crores. A provision of Rs. 108 crores has been made for the development of ports which includes construction of additional berths at Kandla, Tuticorin and Visakhapatnam.

58. In tune with our drive to improve and modernise communication facilities, it is proposed to extend 2 lakhs direct telephone connections during 1981-82. An outlay of Rs. 518 crores for Posts and Telegraphs including communications has been provided in the Plan.

59. An outlay of Rs. 390 crores is being provided for chemicals and fertilisers which includes substantial provision for the gas-based fertiliser projects at Thal Vaishet, Hazira and Namrup. Proposals for new nitrogenous and phosphatic fertiliser plants are also being finalised.

60. Village and small industries have an immense potential for providing employment while sustaining the traditional arts and skills of the village artisans and craftsmen. An outlay of Rs. 162 crores has been earmarked for these sectors adding to the outlays of Rs. 153 crores in the Plans of the States and Union Territories.

61. Finally I come to the all important question of population growth. All our efforts at eradicating poverty will be frustrated if we cannot reduce the rate of population growth. We have taken up revitalisation of the Family Welfare Programme in earnest. A provision of Rs. 155 crores is being made for this programme in 1981-82.

62. The Government is deeply concerned about the lack of adequate communication facilities in the North-East. We have therefore, decided to take up six National Highways with a total length of 1700 Kms, at a total cost of Rs. 70 crores. It has also been decided to establish a more direct connection from Nowgong to Dimapur on National Highway No. 36 at a cost of Rs. 16 crores. Certain missing links on the road running along the Indo-Bangladesh Border in Meghalaya will be completed at a cost of Rs. 26 crores. Railway facilities in this area are also being augmented. Hon'ble Members are aware that the Third Level Air Service has already started functioning in the North-Eastern Region.

63. Non-Plan expenditure has been subjected to careful scrutiny to keep it to the minimum. Defence expenditure is estimated at Rs. 4200 crores as against Rs. 3800 crores in the current year. I am sure the House will agree with me that in these difficult times the reasonable requirements of defence should be fully met.

64. A provision of Rs. 3124 crores is being made for interest payments as against Rs. 2665 crores in the current year, the increase being mainly on account of internal debt. Due to the increase in prices of naphtha and other inputs, the cost of production of indigenous fertilisers has also gone up. The cost of imported fertilisers has also increased. Accordingly, the Budget for 1981-82 provides for a higher subsidy on fertilisers of Rs. 679 crores as against Rs. 466 crores in the current year.

65. Provision for non-Plan loans to public sector undertakings has been reduced from Rs. 454 crores in the current year to Rs. 318 crores in view of the anticipated improvement in their performance and financial position in the next year. A lump sum provision of Rs. 200 crores is also being made in next year's Budget to cover the incidence of additional expenditure on dearness allowance to Central Government employees. In future, dearness relief to pensioners will be paid at the rate of 2.5 per cent of pension for each 8 point rise in the consumer price index instead of at the rate of 5 per cent for each 16 point rise as at present. The procedure for payment of dearness relief to pensioners is also being streamlined. These changes will mitigate the hardships faced by pensioners.

66. Hon'ble Members are aware that India will have the privilege of holding the next Asian Games in 1982 in the capital. The expenditure necessary next year for the games is being provided in the budgets of the Ministries concerned. Most of the expenditure will be on improvement and creation of permanent assets like roads, stadia, and other sports facilities.

67. The total non-Plan expenditure for 1981-82 is estimated at Rs. 15100 crores compared with Rs. 13736 crores in the current year.

68. As regards receipts for 1981-82, the gross tax revenues at the existing rates of taxation are estimated at Rs. 14472 crores compared with Rs. 13133 crores in the current year, showing an increase of Rs. 1339 crores over the Revised estimates. The States' share of taxes in 1981-82 is estimated at Rs. 4206 crores compared with Rs. 3792 crores in the current year. Consequently the Centre's net tax revenue will be Rs. 10266 crores as against Rs. 9341 crores in the current year.

69. The receipts from market loans are estimated at Rs. 2800 crores compared with Rs. 2604 crores in the current year. Small savings are estimated to yield Rs. 1250 crores next year compared with Rs. 1100 crores in the current year. External assistance, net of loan repayments is estimated at Rs. 1379 crores as compared with Rs. 1258 crores in the current year. A credit of Rs. 800 crores has also been taken for receipt from sale of Special Bearer Bonds in the next financial year.

70. Taking into account the effect of the changes in the fare and freight rates of railways, changes in the P&T tariff to which I will refer a little later and the continuance of the Compulsory Deposit Scheme for Income-tax Payers beyond 31-3-1981, the total receipts for 1981-82 are estimated at Rs. 23061 crores. The total expenditure for next year is estimated at Rs. 24871 crores. The overall budgetary gap at the existing rates of taxation will thus be Rs. 1810 crores.

PART B

71. Income-tax and other direct taxes are important instruments for raising resources and reducing disparities. We propose to achieve these objectives by plugging of legal loopholes and effective administration rather than by enhancement of rates which often leads to tax evasion and generation of black money. My proposals are also designed to further our Party's avowed policy of affording relief to the middle classes in these difficult times.

72. Hon'ble Members will recall that last year the exemption limit for income-tax on personal incomes was raised to Rs. 12,000. But the nil slab rate was retained at Rs. 8,000. The House will be glad to know that I propose to raise the exemption limit for income-tax in the case of non-corporate taxpayers other than registered firms and Hindu undivided families with one or more members having separate income exceeding the exemption limit, from Rs. 12,000 to Rs. 15,000. With a view to providing significant relief to middle income

groups, I further propose to raise the nil rate slab from Rs. 8,000 to Rs. 15,000 and also restructure the rate schedule up to Rs. 30,000. The rate of income-tax on the slab of Rs. 15,001 to Rs. 25,000 will be 30 per cent, and on the slab of Rs. 25,001 to Rs. 30,000, 34 per cent. The rates of income-tax on higher slabs will remain unchanged. As a result of these changes, about 14 lakhs of taxpayers will go out of the income-tax net. I venture to claim that never have so many people been freed from the burden of income taxation at one stroke. Apart from this, another 11.5 lakhs of taxpayers in the income brackets of Rs. 15,001 to Rs. 30,000 will also get varying degrees of relief. The reduction in the tax liability at income level of Rs. 15,000 will be Rs. 990; at Rs. 20,000, Rs. 495 and at Rs. 25,000, Rs. 220. There will be no change in the tax liability in the case of taxpayers having income exceeding Rs. 30,000. Thus I have provided in one year income-tax exemption and/or reduction to over 25 lakhs of income-tax assesses out of about 40 lakhs of assesses in the country.

73. At present, salaried taxpayers are entitled to a standard deduction in an amount equal to 20 per cent, of the salary up to Rs. 10,000 and 10 per cent, of the balance subject to an overall ceiling limit of Rs. 3,500. These limits were fixed in 1974. In view of the subsequent rise in prices and as a means of relief to salaried taxpayers, I propose to enhance the rate of standard deduction to 20 per cent, subject to a higher ceiling of Rs. 5,000. Hon'ble Members will be happy to know that this benefit will be applicable to pensioners also. At present, employees in receipt of conveyance allowance are entitled to a standard deduction of Rs. 1,000 only. It is now proposed that they should be given the benefit of full standard deduction.

74. In view of the urgent need to raise the level of savings in the economy, I propose to continue the Compulsory Deposit Scheme for Income-tax Payers for another two years.

75. The corporate sector has a crucial role to play in the growth of the national economy. I have earlier in my speech referred to the various steps taken for improving the climate for investment in industry. I now propose to reduce by 5 per cent. the surcharge on income-tax payable by all classes of companies i.e. from 7.5 per cent. to 2.5 per cent. This will add to the internal availability of funds in the corporate sector and should improve the scope for investment financing from their own resources. This step will reinforce the impact of the measures which I have indicated earlier for mobilising financial resources for industrial investment.

76. As Hon'ble Members are aware, all categories of taxpayers are required to pay advance tax on pay-as-you-earn basis. Surtax is, however, not payable by companies in advance. I propose to remove this anomaly and provide that surtax will also be payable in advance during the financial year preceding the relevant assessment year.

77. The Eleventh Schedule to the Income-tax Act contains a list of industries which do not qualify for specified investment related tax concessions under the Income-tax Act. For example, investment allowance or tax holiday is not admissible in respect of these industries unless they are in the small-scale sector. Industries included in this Schedule were originally considered to be of low priority. However, on reviewing the list, I do not find any justification for treating many of the listed industries as of low priority. Accordingly, 14 groups of industries will be removed from this Schedule and will now become eligible for the specified tax concessions. These industries include electric fans, pressure cookers, glass and glassware, pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers, chinaware and porcelainware, mosaic tiles and glazed tiles, synthetic detergents, amplifiers or any other apparatus used for addressing the public vacuum flasks and other vacuum vessels, etc. These industries, some of which have export potential, will now become eligible for the specified tax concessions.

78. Hon'ble Members will recall that the Government had taken several measures last year to curb the use of private discretionary trusts as a device for tax avoidance. Another

tax avoidance device that has come to the notice of the Government is the creation of oral trusts. With a view to checking this abuse, I propose to subject oral trusts to income-tax at the maximum marginal rate and to wealth-tax at the flat rate of 3 per cent, or at the appropriate rate applicable in the case of an individual, whichever course is more beneficial to the revenue. This proposal will take effect from the assessment year 1981-82.

79. Another device being used for avoiding proper tax liability is the creation of associations of persons without defining the shares of members. This enables the creation of a large number of taxable entities which, under the existing law, will be chargeable to income-tax separately. I now propose that such associations of persons be charged to income-tax at the maximum marginal rate and to wealth-tax at the flat rate of 3 per cent, or at the appropriate rate applicable in the case of an individual, whichever is higher. This proposal will also take effect from the assessment year 1981-82.

80. Earlier in my speech, I have referred to the prospective participation of foreign companies in the field of oil exploration and production. In this connection, it is necessary to take several steps relating to tax matters. Firstly, it is proposed to extend the Income-tax Act and the Companies (Profits) Surtax Act to the off-shore areas. Secondly, it is proposed to insert suitable provisions in the Income-tax Act and the Companies (Profits) Surtax Act to enable the Central Government to provide, by a notification in the Official Gazette for an exemption, reduction in rate or other modification in respect of income-tax or surtax in favour of any class of persons engaged in the business of mineral oils and gas in association with the Central Government or any person authorised by it. Notifications under the new provisions when made will be placed on the Table of both the Houses of Parliament. It is also proposed to amend section 42 of the Income-tax Act relating to special provision for deductions in the case of business of the prospecting for or extraction or production of mineral oils so as to extend its scope to cover cases where the Government itself does not participate in such business but does so through any person authorised by it.

81. While the search for additional quantities of oil should continue with unabated vigour, there is also an urgent need to accelerate the development and use of renewable energy resources and to promote their utilisation. The renewable energy sources which have already been brought to the threshold of commercial use by our scientists and engineers include solar, biomass and wind energy. Some fiscal incentives to promote use of these non-conventional forms of energy are called for. I, therefore, propose to enhance the depreciation allowance on machinery or plant installed for manufacturing renewable energy devices and systems from 10 per cent. available at present to 30 per cent. Depreciation on renewal energy devices and systems used for business or profession will also be allowed at the enhanced rate. Other measures under contemplation by the Government include loans to the relevant industries on suitable terms from financial institutions and exemption from certain taxes and duties.

82. I had earlier in my speech referred to the imperative need to promote our exports in view of our difficult balance of payments situation. To encourage establishment of export-oriented industries in the Free Trade Zone, the Government proposes to allow complete tax holiday in respect of units set up in these Zones for an initial period of five years in lieu of other concessions.

83. Tea is one of our important export-oriented industries. At present, development allowance equal to 50 per cent. of the expenditure incurred on plantation of tea bushes in any new area or on any land which has been previously abandoned is allowed in computing the income from tea business. For this purpose, the expenditure qualifying for development allowance is restricted to Rs. 12,500 per hectare of land situated in hilly areas and Rs. 10,000 per hectare in other areas. Having regard to the increase in the cost of planting in recent years, I propose to raise these ceiling limits to Rs. 40,000 per hectare of land situated in Darjeeling

district Rs. 35,000 per hectare in respect of land situated in other hilly areas and Rs. 30,000 per hectare in plains.

84. Under section 35B of the Income-tax Act, domestic companies and non-corporate taxpayers resident in India are entitled to a weighted deduction in the computation of the taxable profits at the rate of one and one-third times the amount of qualifying expenditure incurred by them on development of export markets. The scope of this provision was curtailed last year as it had been misused for claiming a weighted deduction in respect of expenditure incurred in India on activities which had no direct relation with the basic objective of development of export markets. In order to guard against such misuse, while at the same time protecting all legitimate effort at export market development, the Government is framing rules which will identify a number of specific activities to be allowed under section 35B. The necessary notification in this behalf will be issued shortly.

85. Electronics is both a labour-intensive and export-oriented industry. I, therefore, propose to include the electronic component industry in the Ninth Schedule to the Income-tax Act and provide that dividends derived by a domestic company from an Indian company engaged exclusively in the manufacture of electronic components will be completely exempt from income-tax.

86. The small-scale industrial undertakings enjoy certain tax concessions under the Income-tax Act. For this purpose, an industrial undertaking is regarded as a small-scale industrial undertaking if the aggregate value of the machinery and plant installed therein as on the last day of the previous year does not exceed Rs. 10 lakhs. I now propose to raise this limit to Rs. 20 lakhs in line with the new definition of a small-scale industry.

87. Under the existing law, in computing taxable income, a deduction equal to 20 per cent. of the profits and gains derived from the business of publication of books is allowed. I propose to extend this concession for a period of five years with effect from assessment year 1981-82.

88. At present, approved financial corporations and public housing finance companies are entitled to a deduction in respect of the specified percentage of income carried to special reserve, subject to certain conditions. The aggregate of the amounts qualifying for such deduction is, however, subject to an overall ceiling equal to the amount of the paid-up share capital. In order to enable such corporations and companies to build up such reserves further, I propose to double the present ceiling.

89. Under the existing law, resident individuals and Hindu undivided families are entitled to a deduction in respect of medical treatment of physically or mentally handicapped dependants. I propose to double the amount of this deduction to Rs. 4,800 in respect of a dependant who is hospitalised for a period of 182 days or more during the relevant accounting year and Rs. 1,200 in other cases. The House will doubtless welcome this concession being given in the International Year for the Disabled Persons.

90. I propose to give some significant concessions under the Estate Duty Act. The present limit of Rs. 50,000 for estate duty was fixed in 1958. I propose to raise it to Rs. 1.5 lakhs the same as under the Wealth-tax Act. I also propose to provide that one residential house or part thereof will be valued for estate duty purposes on the same basis as for the purposes of wealth-tax. Since the Estate Duty Act can be amended only with the concurrence of State Legislatures, a Bill for giving effect to these proposals will be introduced later.

91. I propose to make certain amendments in the income-tax Act to upgrade the qualifications for appointment as members of the Income-tax Appellate Tribunal.

92. Other amendments to the direct tax laws are of minor significance. I would not like to take up the time of the House by referring to them in detail here.

93. The reduction in the rates and other concessions in respect of income-tax on personal incomes would result in a loss of Rs. 146 crores in a full year and Rs. 115 crores during 1981-82. Having regard to the pattern of sharing of income-tax between Centre and States, these concessions will entail a loss of revenue of Rs. 29 crores to the Centre in 1981-82. The loss of revenue on account of reduction in the rates of corporation tax and other concessions to companies will largely be balanced by the payment of surtax in advance by companies. I am, therefore, not assuming any loss of revenue on this score for 1981-82.

94. I now turn to my proposals on indirect taxes. My basic approach is that additional revenue should flow largely from increased production. However, there is need to mobilise additional resources to finance the Sixth Plan. While seeking to raise additional resources, I have nevertheless kept in mind the imperative need to avoid hardship to the middle and poorer sections of consumers and to provide a larger measure of relief to the small-scale sector of our industry.

95. Taking Customs duties first, my principal proposal relates to auxiliary duties of customs. This duty has been levied on an annual basis since the 1973 Budget. While continuing this levy I also propose to raise the rates of auxiliary duties as a measure of additional resource mobilisation. In recent years we have been following a fairly liberal import policy. The difficult balance of payments outlook points to the need for conserving foreign exchange. The tariff mechanism judiciously used, can help conserve foreign exchange and also raise some revenue. I, therefore, propose to increase the rates of auxiliary duties by 5 per cent ad valorem on all categories of imports with a few well-merited exceptions. This will obviate a sharp increase in the landed cost of any particular article.

96. Auxiliary duties of customs are now leviable on imported goods broadly on a three-tier basis. Items subject to a basic duty upto 60 per cent ad valorem, for example basic raw materials, bear an auxiliary duty of 5 per cent ad valorem; on items such as semi-processed goods and intermediates, where the rate of basic duty is 60 per cent ad valorem or above but less than 100 per cent, the rate of auxiliary duty is 15 per cent ad valorem; and where the rate of basic duty is 100 per cent ad valorem or above such as on finished and consumer goods, the rate of auxiliary duty is 20 per cent ad valorem. In other cases the rate of auxiliary duty is 5 per cent ad valorem, except crude petroleum on which the rate is Rs. 9.50 per metric tonne. There are also some items which are fully exempt from auxiliary duty. My proposal is to increase the rate of auxiliary duty to 10 per cent ad valorem wherever the rate of auxiliary duty is now 5 per cent to 20 per cent ad valorem wherever the rate is now 15 per cent; and to 25 per cent ad valorem wherever the rate is now 20 per cent. I do not, however, propose to increase the auxiliary duty on crude petroleum.

97. In line with the approach I have explained, I propose to withdraw the present full exemption from auxiliary duties of customs in respect of certain items of capital equipment and subject them to auxiliary duty of customs at the rate of 5 per cent ad valorem. This increase would cover, among other things, imports of machinery as 'project imports' as also items of machinery on which the concessional rate of 25 per cent ad valorem is applied. This measure would, apart from yielding additional revenue, afford some additional protection to the indigenous machine building industry which has, of late, had to face a significant escalation in input costs.

98. I said earlier that I would exclude some items from the proposed increase in the auxiliary duties of customs. Imports of essential items like edible oil will be exempted from the proposed increase. Bulk petroleum products such as kerosene and high speed diesel oil and steel imported for buffer stock operations will also not attract the increased levy. Items on which import duty rates have been changed

in the recent past with a view to maintaining parity with prices of domestic products have also been kept out of the purview of the increased levy. Further, keeping in view our commitments under the General Agreement on Tariffs and Trade, I propose to give up the auxiliary duty in respect of three items involving a small revenue sacrifice. Further details of the proposals are available in the Budget Papers.

99. These proposals are expected to yield an additional revenue of about Rs. 250 crores.

100. My next proposal relates to levy of import duty on newsprint. At present this item is fully exempt. There is a large foreign exchange outgo on imports of newsprint. There is no reason why this commodity should not bear a moderate rate of customs duty. I, therefore, propose to impose an effective customs duty of 15 per cent ad valorem on imported newsprint. I expect this measure to yield an additional revenue of about Rs. 21 crores.

101. Imports of stainless steel bars and wire rods now attract a duty of 75 per cent because they have industrial applications. But there is reason to believe that some of these imports are being diverted for re-rolling into strips and sheets used in the manufacture of utensils. I, therefore, propose to raise the effective customs duty on stainless steel bars, rods and wire rods from 75 per cent to 175 per cent ad valorem. I have, however, taken care to see that this increase does not affect imports of stainless steel wire rods which are used for the drawing of wires. This measure is expected to yield an additional revenue of Rs. 5 crores.

102. I also propose to raise the basic customs duty on plain shaft bearings from 60 per cent to 100 per cent ad valorem. This increase should help to restrict large scale imports of bearings such as thin-walled bearings, which have been affecting the indigenous industry. This proposal is expected to yield an additional revenue of Rs. 2.75 crores. On similar considerations it is proposed to raise the basic customs duty on computers and computer peripherals from 40 per cent to 50 per cent ad valorem. The likely revenue gain from this increase would be Rs. 1 crore.

103. I will now come to excise duties. The House will recall that in 1978 the Additional Excise Duties (Textiles and Textile Articles) Act was passed, in terms of which an additional duty excise was levied on certain textiles and textile articles at 10 per cent of the basic excise duty leviable. The revenue from this excise levy was intended to meet the expenditure incurred by way of subsidy on controlled cloth. The production of controlled cloth is being stepped up, with emphasis on larger production of dhotis and sarees which are of special significance to the poorer sections of society, particularly in rural areas. As a result, the provision for subsidy under this scheme would rise to nearly Rs. 100 crores in the coming year. The revenue at the existing rate of additional excise duty is only about Rs. 66 crores. I, therefore, propose to raise the rate of additional excise duty from 10 per cent to 15 per cent of the basic excise duty on all the items which are now covered by the levy. This would yield an additional amount of about Rs. 33 crores and help finance the increase outlay on controlled cloth.

104. As regards special excise duties, I propose only to continue them at the existing rates. The exemptions in force are also being continued.

105. My remaining proposals under Union excise duties are mainly designed to achieve simplification and greater clarity.

106. Hon'ble Members would be aware that there is a graded structure of duty on matches, the mechanised sector paying Rs. 7.20 per gross boxes, the middle sector paying Rs. 4.50 and the cottage sector Rs. 1.60. In the light of the report of the Dandekar Committee and a special study made by the Government, it has become necessary to discourage a tendency of middle sector units towards mechanisation of certain labour-intensive processes. Accordingly, I propose that the concessional rates of duty i.e. Rs. 4.50 for middle sector units and Rs. 1.60 for cottage units, will not be available if power is used in the labour-intensive process

of frame-filling, dipping, splints in match composition, box making, box fitting, labelling and banderolling and packaging. If such units use power for any of the above process, they will be liable to a duty rate of Rs. 5.50 per gross boxes, which would be intermediate between the rate of Rs. 7.20 applicable to the fully mechanised sector and Rs. 4.50 now applicable to the non-mechanised middle sector. I would like to stress that this is not intended as a revenue measure. It is intended only to protect through the excise mechanism, the employment potential of the non-mechanised sector.

107. With a view to preventing the possible infiltration of the middle sector into the cottage sector and in order to ensure that the benefit of the lowest rate of duty accrues to genuine cottage sector units, it is proposed to reimpose a ceiling on the clearances by cottage sector units at concessional rates. The new ceiling, which is proposed to be fixed at 120 million matches per unit per annum, is much more liberal than the ceiling of 75 million that existed prior to the 1980 Budget. The pattern of production and clearance will be kept under watch and this ceiling will be reviewed if circumstances so warrant. The changes I have proposed are fair to all segments of the industry and are designed to promote both employment and production in the best possible manner.

108. Another rationalisation measure relates to the concession available to manufacturers of goods falling under Tariff Item 68, who undertake work on 'job' basis. Under the present scheme, duty is being effectively collected only on the 'job charges' paid by the principal manufacturer to the job worker. In the operation of the scheme, however, several difficulties have been experienced particularly on the question of what is 'job work'. There have been cases where some manufacturers have taken undue advantage of the concession. I, therefore, propose to replace the present scheme by one in which, instead of levying duty separately on the job charges paid to the job worker, the duty will be paid by the principal manufacturer on the value of the finished goods. This step should be generally welcomed by ancillary units which undertake work on job basis.

109. I also propose to rationalise the Central Excise tariff entry and the rate structure relating to tyres with a view to making the legislative intent clearer and minimising the scope for disputes in classification and assessment, particularly in regard to off-the-road tyres used in bulldozers, scrapers and other earth moving equipments. While proposing the necessary amendments, I have taken care to maintain the existing rates of duties and duty concessions in respect of tyres both for agricultural tractors and their trailers.

110. The other major area where rationalisation of the tariff entries has been proposed is in regard to non-ferrous metals under the respective entries in the Central Excise Tariff. There has been considerable debate and dispute on the question of assessment of waste and scrap of these metals. To set these at rest it is proposed to specifically cover waste and scrap of these metals under the respective tariff entries.

111. In addition to the above, a few other amendments to certain tariff entries as also the insertion of a separate tariff item for polyester film have been proposed. The details of these changes may be seen from the Budget papers.

112. I now turn to a proposal which seeks to fulfil a long-standing demand of State Governments. The scheme of levy of additional excise duty in lieu of sales-tax is at present applicable to sugar, tobacco and some textile items. The National Development Council had recommended that the revenue yield from Central excise duties and additional excise duties be in the ratio of 2:1 as far as possible. At a Conference of Chief Ministers, I gave an assurance that an effort would be made to achieve this ratio in respect of these commodities as a whole.

113. I have considered how best this assurance can be fulfilled. The simplest solution will be to make a change in the ratio for sharing of revenues from cigarettes as between the Centre and the States. As against the present ratio of 76 : 24 between basic excise duty and additional excise duty in the composite rate applicable to cigarettes, the ratio is proposed to be changed to 72.5 : 27.5. This will be combined with a uniform increase in the specific duty element in the composite

rate from Rs. 21.00 to Rs. 21.25 per thousand. The overall revenue from cigarettes will remain practically unchanged. There should, therefore, be no justification for manufacturers to mark up the prices of cigarettes. With these changes, the overall ratio between the yield from basic and special excise duties on the one hand and additional excise duties on the other is expected to improve to 2 : 1 taking the three items sugar, tobacco and textiles together. This will result in a transfer of about Rs. 21.72 crores from revenues under Central Excise to the revenue under additional excise duty.

114. I have also a minor proposal which is basically of interest to the State Governments. Under the Medicinal and Toilet Preparations Act, 1959, excise duties are leviable on medicines and toilet preparations which contain alcohol, narcotics and narcotic drugs. Certain changes have been proposed in the Act with a view to effecting a switch over to the metric system and also to eliminate avoidance of duty in certain cases. The changes proposed, however, have very little revenue significance.

115. I shall now turn to concessions in the area of indirect taxes. This Government is committed to the pursuit of a vigorous policy of promoting small scale industry in the interest both of employment and broader development of entrepreneurship. Accordingly, I propose to increase the duty exemption limit under the general scheme of excise duty concessions applicable to 72 excisable commodities from Rs. 5 lakhs in terms of value of clearances to Rs. 7.5 lakhs. Clearances in excess of Rs. 7.5 lakhs will continue to benefit from the existing concessional duty limited to three-fourths of the applicable rates of excise duty up to a clearance of Rs. 15 lakhs in a financial year as at present. This measure should benefit a substantial number of small manufacturers and enable them to compete more effectively with large units. I am sure that all sections of the House will welcome this enlargement of the scheme of concessions enjoyed by small scale industry.

116. Under the excise duty concessions available at present to small manufacturers of some products, notably Item 68 goods and specified electronic goods, one of the criteria for eligibility is the value of investment in plant and machinery. I propose to increase the eligibility limit of such investment from the present figure of Rs. 10 lakhs to Rs. 20 lakhs, in line with the revised definition of 'small scale units' under the new Industrial Policy. Here again I am confident that my proposal will be welcomed by all the Hon'ble Members.

117. In the last Budget I had announced wide ranging duty concessions with a view to encouraging the development of the electronics industry. As a further step in this direction, I propose to extend the scope of the import duty concessions so as to cover 59 new items of capital equipment and 23 new items of raw materials and components used by the electronics industry.

118. At present, the handloom sector of the woollen industry does not enjoy any special duty concessions. This sector has a good growth potential. I, therefore, propose to reduce substantially the processing stage duty on woollen fabrics produced on handlooms on the lines of the concessions which are available to cotton fabrics produced on handlooms.

119. I also propose to extend the concessional import duty of 25 per cent ad valorem to a few more important drug intermediates. This step should induce indigenous manufacturers to go in for production of more basic drugs.

120. Last year, I had fully exempted cotton and cotton-viscose blend hosiery from excise duty. I now propose to extend this exemption to all hosiery articles falling under Item 68 of the Central Excise Tariff.

121. Another duty concession relates to 'flocked' fabrics where the excise duty is being reduced from the present level of the base fabric duty plus 30 per cent ad valorem to the base fabric duty plus 15 per cent ad valorem on the consideration that the present duty burden is heavier than warranted, particularly on flock-printed fabrics. Further, no colour

scanners for the printing industry, the basic customs duty is being reduced from 100 per cent ad valorem to 60 per cent ad valorem.

122. In this International Year of the Disabled, it is fitting that appropriate tax relief measures should be extended to our handicapped brethren. Artificial limbs and rehabilitation aids for the handicapped are already exempted from Central excise duty under Item 68. I now propose to exempt fully from excise duty Braille watches for the use of the blind.

123. I also propose to exempt from excise duty Braille paper which is necessary for printing books for use by the blind.

124. I further propose to substantially reduce the customs duty on hearing aids and Braille watches imported for personal use by post or air.

125. The increased levy of auxiliary duties of customs to which I have earlier referred will not be applied to goods such as orthopaedic appliances, Braille watches and parts, tricycles for the crippled, hearing aids and parts. I am sure that this House will wholeheartedly endorse these proposals.

126. The various concessions and reliefs in excise and customs duties which I have announced will entail a sacrifice of revenue of Rs. 9.35 crores in a full year.

127. My taxation proposals will yield a sum of about Rs. 35.57 crores in a full year by way of excise duties and Rs. 285.00 crores by way of customs duties. The concessions I have announced add up to Rs. 7.05 crores on the excise side and Rs. 2.30 crores on the customs side. The net yield is, therefore, Rs. 28.52 crores from excise duties and Rs. 282.70 crores from customs duties. The accrual to the Central Exchequer in a full year will be Rs. 300.50 crores.

128. I hope it would not have escaped the notice of Hon'ble Members that this is perhaps the first Budget in recent years in which no increase has been effected in excise duties for raising general revenues.

129. I would now like to say a few words on behalf of my Hon'ble colleague, the Minister of Communications. A substantial programme of development of telecommunication facilities is envisaged during the Sixth Five Year Plan. It is, therefore, appropriate that the Department should generate internal resources to a reasonable extent for financing its Plan. The additional dearness allowance sanctioned to employees and other increases in the cost of operations have already eroded the existing surplus of the Department. It has, therefore, become necessary to revise certain telecommunication tariffs. At present the rate of telephone call charge in measured rate telephone system is 30 paise per call unit for calls exceeding 250 but not more than 1750 in a quarter. It is proposed to increase this charge to 40 paise per call unit. The manual trunk call charges for calls of ordinary category for a unit period of 3 minutes in the distance slabs of 100 to 200 kilometres are being increased from Rs. 6 to Rs. 8 and in the distance slab of 200 to 500 kilometres from Rs. 10 to Rs. 12. These measures are estimated to yield Rs. 35.78 crores in a full year. The additional revenue during 1981-82 will be of the order of Rs. 20 crores and has been taken into account in estimating the receipts of Posts and Telegraphs. It is also proposed to increase the rates of deposits for telephone connections under 'Own Your Telephone' system. This revision will yield about Rs. 5 crores to the Government by way of additional deposits in 1981-82. The details of these revisions are shown in a memorandum which is being circulated along with the Budget papers. The changes will be given effect to from a date to be notified after the Finance Bill is passed by Parliament. There will be no change in either postal or telegraph rates.

130. I had earlier stated that the resources gap estimated at existing rates of taxation is Rs. 1810 crores. The various tax measures I have presented, together with the reliefs offered, will yield net additional revenue of Rs. 271 crores to the Centre. This leaves an uncovered deficit of Rs. 1539 crores. This deficit may appear large, but taking a total view of the economic situation I believe it is within the limits

of fiscal prudence. The inflationary potential of the Budget must be viewed in the context of the full package of policy measures which I have outlined. This package contains many incentives for higher production and increased utilisation of capacity. This should stimulate a considerable supply response during the coming year and as I have mentioned, signs of this upturn are already evident. I attach great importance to expanded supplies as the critical element in keeping inflationary pressures in check. The package also contains important incentives to savings which will undoubtedly help in this regard. Furthermore, monetary and credit policies will be so designed as to ensure that Government recourse to deficit financing takes place within a balanced and measured overall expansion of credit in the system.

131. Mr. Speaker, Sir, the economic situation remains difficult and yet full of great opportunities for development and growth. I have tried to present a Budget which gives maximum support to forces that can move us forward on the path of growth with stability and social justice. It sets the stage for all of us to work towards the achievement of our economic and social goals so clearly laid out in the Sixth Plan. Economic policy can only do this much. Hard work, discipline and the innate good sense of the people of this ancient land must do the rest.

132. Sir, I commend this Budget to the House.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.